

[2023] 4 एस. सी. आर 635

प्रेम किशन और ओआरएस।

वी.

ब्रह्म प्रकाश और ओआरएस।

(सिविल अपील सं. 1948

2013)

29 मार्च, 2023

[सुधांशु धूलिया और जे. बी. पारदीवाला, जे. जे.]

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908-एस। 11 , या. 7 आर. 11, या 9 आर. 8, या। 17 आर. 3-दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम, 1958। 14 (1) (अ)-द

मकान मालिक (मूल वादी) ने प्रत्यर्थी (किरायेदार) के खिलाफ बेदखली याचिका दायर की प्रत्यर्थी ने लिखित बयान दायर किया और मकान मालिक और किरायेदार के संबंधों से इनकार किया-इसके बाद, मकान मालिक पक्षकारों के बीच मकान मालिक और किरायेदार का संबंध स्थापित करने के उद्देश्य से किराया नियंत्रक के सामने पेश होने में विफल रहा-किराया नियंत्रक बेदखली याचिका को खारिज करने के लिए आगे बढ़ा और उसे अपील के माध्यम से चुनौती नहीं दी गई -

मकान मालिक की मृत्यु के बाद, अपीलार्थी (हित में उत्तराधिकारी) ने एक और बेदखली याचिका दायर की, प्रतिवादी ने धारा 11 के तहत न्यायिक याचिका दायर की और या के तहत एक आवेदन को प्राथमिकता दी। 7 आर. 11 अभियोग की अस्वीकृति के लिए-अतिरिक्त किराया नियंत्रक ने अस्वीकार करने से इनकार कर दिया

वाद-इससे व्यथित होकर, प्रत्यर्थी ने उच्च न्यायालय के समक्ष एक दीवानी पुनरीक्षण याचिका को प्राथमिकता दी और उसी की अनुमति उच्च न्यायालय द्वारा दी गई।

उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करते हुए कि अपीलार्थी द्वारा दायर नई बेदखली याचिका न्यायिक प्रक्रिया के सिद्धांतों से प्रभावित है क्योंकि मकान मालिक को साक्ष्य देने का अवसर दिया गया था और वह न्यायालय में कोई साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफल रहा है, इसे निर्णय के रूप में लिया जाना चाहिए।

संहिता की धारा 11 के प्रयोजन के लिए Or.17 नियम 3 के तहत गुणागुण पर-अपील पर, अभिनिर्धारित किया गया: उच्च न्यायालय ने यह विचार रखने में त्रुटि की कि अतिरिक्त किराया नियंत्रक द्वारा पारित आदेश को या के नियम 3 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए पारित किया गया कहा जा सकता है। 17- आदेश का उद्देश्य बर्खास्तगी नहीं था

चूक या गुण-दोष पर और इसका अर्थ इसके अलावा नहीं लिया जा सकता है कि यह क्या था-इसके अलावा, किराया नियंत्रक का आदेश मुकदमे का अंतिम निपटान नहीं था और उसने जो किया वह यह था कि

केवल कार्यवाहियों को रोक दिया और इसने और कुछ नहीं किया और इसलिए यह या के अर्थ में मुकदमे का अंतिम निर्णय नहीं है। 9 नियम 8 और या। 17 सी. पी. सी. के नियम 3 का जवाब-सूट को पुनर्जीवित किया गया है।

[2023] 4 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908-जब यह बाद के मुकदमे में न्यायिक अधिकार नहीं होगा-आयोजित: जहाँ पूर्व मुकदमा अधिकारिता के अभाव में या न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया जाता है।

वादी की उपस्थिति, या गैर-सहयोगी या गलत के आधार पर

पक्षकारों की संलिप्तता या बहुभिन्नता, या इस आधार पर कि मुकदमा बुरी तरह से तैयार किया गया था, या किसी तकनीकी गलती के आधार पर, या वादी की ओर से प्रोबेट या प्रशासन पत्र या उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में विफलता के लिए जब वादी को एक डिक्री का हकदार बनाने के लिए कानून द्वारा इसकी आवश्यकता होती है, या लागत के लिए प्रतिभूति प्रदान करने में विफलता के लिए, या अनुचित मूल्यांकन के आधार पर, या एक शिकायत पर अतिरिक्त अदालत शुल्क का भुगतान करने में विफलता के लिए जो था

अवमूल्यन, या कार्रवाई के कारण के अभाव के लिए, या इस आधार पर कि यह अपरिपक्व है और बर्खास्तगी की पुष्टि अपील (यदि कोई हो) में की जाती है, निर्णय, गुण-दोष पर नहीं होने के कारण, बाद के मुकदमे में न्यायिक नहीं होगा।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने पकड़ना: 1. आवेदन तय करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत

सी. पी. सी. के आदेश 7 नियम 11 (डी) के तहत संक्षेप में निम्नलिखित कहा जा सकता है: - (i) किसी वाद को इस आधार पर अस्वीकार करने के लिए कि वाद किसी भी कानून द्वारा वर्जित है, केवल वाद में अभिकथनों को संदर्भित करना होगा।

(ii) वाद में प्रतिवादी द्वारा किए गए बचाव पर आवेदन के गुण-दोष का निर्णय करते समय विचार नहीं किया जाना चाहिए; (iii) यह निर्धारित करने के लिए कि क्या कोई वाद न्यायिक प्रक्रिया द्वारा वर्जित है, यह आवश्यक है कि (i) पिछले वाद का निर्णय किया जाए, (ii) वाद में मुद्दों का निर्णय किया जाए।

शीर्षक; और (iv) कि इन मुद्दों पर निर्णय लिया गया था और अंत में बाद के मुकदमे का परीक्षण करने के लिए सक्षम अदालत द्वारा निर्णय लिया गया था; और (iv) चूंकि न्यायिक याचिका के निर्णय के लिए 'पिछले मुकदमे' में दलीलों, मुद्दों और निर्णय पर विचार करने की आवश्यकता होती है, इसलिए ऐसी याचिका आदेश 7 नियम 11 (डी) के दायरे से बाहर होगी, जहां केवल वाद में दिए गए बयानों का ही अध्ययन करना होगा। [पैरा 33] [653 एफ-एच; 654-ए-बी] 2. सी. पी. सी. की धारा 11 के तहत रेज़ जुडिकाटा के सामान्य सिद्धांत में निर्णय की निर्णायकता के नियम हैं, लेकिन रेज़ के लिए

न्यायपालिका को लागू करने के लिए, बाद के मुकदमे में प्रत्यक्ष रूप से और काफी हद तक जारी किया गया मामला वही मामला होना चाहिए जो सीधे पी. आर. ई. एम. किसान और ओ. आर. एस. था।

वी. ब्रह्म प्रकाश और ओआरएस।

और काफी हद तक पूर्व वाद में जारी किया गया। इसके अलावा, मुकदमे का निर्णय गुण-दोष के आधार पर किया जाना चाहिए था और निर्णय को अंतिम रूप दिया जाना चाहिए था। जहां पहला मुकदमा निचली अदालत द्वारा अधिकारिता के अभाव में, या वादी की उपस्थिति में चूक के लिए, या पक्षों के गैर-सहयोगी या गलत सहयोगी या बहुभिन्नता के आधार पर, या इस आधार पर खारिज कर दिया जाता है कि मुकदमा था बुरी तरह से तैयार किया गया, या किसी तकनीकी गलती के आधार पर, या वादी की ओर से प्रोबेट या पत्र प्रस्तुत करने में विफलता के लिए

प्रशासन या उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जब वादी को एक डिक्री का हकदार बनाने के लिए कानून द्वारा इसकी आवश्यकता होती है, या लागत के लिए प्रतिभूति प्रदान करने में विफलता के लिए, या अनुचित मूल्यांकन के आधार पर, या एक शिकायत पर अतिरिक्त अदालत शुल्क का भुगतान करने में विफलता के लिए जो था

अवमूल्यन, या कार्रवाई के कारण के अभाव के लिए, या इस आधार पर कि यह अपरिपक्व है और बर्खास्तगी की पुष्टि अपील (यदि कोई हो) में की जाती है, निर्णय, गुण-दोष पर नहीं होने के कारण, बाद के मुकदमे में न्यायिक नहीं होगा। [पैरा 34] [654-सी-ई]

3. मामले में, पहली बेदखली याचिका दायर किए जाने के बाद, प्रतिवादियों ने अपना लिखित बयान दायर किया

मकान मालिक और किरायेदार के संबंध को अस्वीकार करना। लिखित बयान के रिकॉर्ड में आने के बाद, वादी द्वारा आगे कोई सबूत नहीं दिया गया। जो कुछ भी अभिलेख में था वह शिकायत में दलीलों के रूप में था। अतिरिक्त किराया नियंत्रक का विचार था कि लिखित बयान रिकॉर्ड में आने के बाद, यह वादी का कर्तव्य था कि वह मकान मालिक किरायेदार संबंध स्थापित या साबित करे।

निवारण के लिए। इसका उपयोग केवल असाधारण मामलों में ही किया जाना चाहिए। मामले की प्रगति से जुड़ी किसी भी चीज़ के लिए सहयोग करने की तैयारी के बिना शारीरिक उपस्थिति गुण-दोष के आधार पर मुकदमे का फैसला करने में कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं करती है और यह उससे भी बदतर है।

अनुपस्थिति। किसी भी आकस्मिकता में, विवेक हमेशा [2023] 4 एस. सी. आर. के पास होता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

न्यायालय क्रमशः नियम 2 या 3 का सहारा लेगा या

के बावजूद नियमित रूप से वाद पर निर्णय लेने के लिए स्थगन
क्रमशः केवल प्रावधानों को सक्षम कर रहे हैं।

डिफ़ॉल्ट। नियम 2 और 3

गुण-दोष के आधार पर वाद का निर्णय करने के लिए केवल नियम 3 में उल्लिखित शर्तों का अस्तित्व ही पर्याप्त नहीं होगा। गुण-दोष पर निर्णय लेने के लिए कुछ सामग्री होनी चाहिए, भले ही सामग्री की तकनीकी रूप से व्याख्या नहीं की जा सकती है

सबूत। कभी-कभी ऐसे मामलों में निर्णय दलीलों, दस्तावेजों और सबूत के बोझ के आधार पर हो सकता है। फिर भी, न्यायालय के लिए यह सराहनीय है कि वह निर्णय द्वारा यह इंगित करे कि निर्णय चूक के लिए या गुण-दोष पर है। नियम 3 द्वारा कवर किए गए मामलों में या नियम 2 के स्पष्टीकरण में न्यायालय का एकमात्र विकल्प केवल गुण-दोष पर निर्णय लेना नहीं है। यदि ऐसी व्याख्या दी जाती है, तो यह उस व्यक्ति के लिए एक अनुचित वरीयता होगी जो जानबूझकर अनुपस्थित रहता है, उस व्यक्ति की तुलना में जो प्रस्तुत करता है लेकिन मामले को आगे बढ़ाने में असमर्थ है। रूप 'और' उपस्थिति 'के अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त अर्थ हैं। वे व्यक्तिगत रूप से या वकील के माध्यम से उपस्थिति का संकेत देते हैं। मामले के संचालन के उद्देश्य से उचित रूप से अधिकृत। नियम 3 तभी लागू होता है जब उपस्थिति मामले के साथ आगे बढ़ने के लिए होती है, लेकिन डिफ़ॉल्ट तीन तरीकों में से किसी एक में किया जाता है।

नियम 2 में उल्लिखित या नियम 2 का स्पष्टीकरण निकाला गया है। वे ऐसे मामले हैं जिनमें अदालत के पास गुण-दोष के आधार पर मामले का फैसला करने के लिए कुछ सामग्री है न कि ऐसे मामले जहां निर्णय केवल चूक के लिए हो सकता है। यह क्रमशः नियम 2 और 3 के संयुक्त अध्ययन और स्पष्टीकरण से स्पष्ट है। इस मामले में, इनमें से कोई भी शर्त मौजूद नहीं थी और निर्णय स्पष्ट रूप से चूक के लिए था। केवल नियम 2 ही आकर्षित करता है। आदेश का उद्देश्य चूक के लिए या गुण-दोष के आधार पर बर्खास्तगी नहीं था और इसका अर्थ इसके अलावा नहीं लिया जा सकता है कि यह क्या था। यह सामान्य है

वाक्यांश विज्ञान; कानूनी वाक्यांश विज्ञान नहीं और इसे अलग नहीं किया जा सकता है इसका सामान्य अर्थ। इसका सामान्य अर्थ यह है कि कार्यवाही बंद कर दी गई थी और मुकदमे को लंबित नहीं माना जाएगा। बाद का विवरण अनावश्यक होगा यदि आदेश मुकदमे के अंतिम निपटारे में से एक था। आदेश का उद्देश्य मुकदमे का अंतिम निपटारा नहीं था। इसने केवल कार्यवाही को रोक दिया। इससे ज्यादा कुछ नहीं किया। यह सी. पी. सी. के आदेश 9 नियम 8 और आदेश 17 नियम 3 के जवाब के अर्थ के भीतर मुकदमे का अंतिम निर्णय नहीं है। [पैरा 50,52,55] [665-ई-जी; 666-बी-जी; 667-एफ-एच; 668-ए] प्रेम किशोर और ओआरएस।

वी. ब्रह्म प्रकाश और ओआरएस

वी. राजेश्वरी बनाम टी. सी. सरवनबावा (2004) 1 एस. सी. सी. 551: [2003] 6 पूरक। एससीआर 927; कमला और अन्य बनाम। केटी.

ईश्वर सा (2008) 12 एस. सी. सी. 661: [2008] 7 एससीआर 39;

चर्च ऑफ क्राइस्ट चैरिटेबल ट्रस्ट एंड एजुकेशनल

चैरिटेबल सोसाइटी v. पोन्नियम्मन एजुकेशनल ट्रस्ट (2012) 8 एस. सी. सी. 706: [2012] 6 एससीआर 404; सौमित्र कुमार सेन बनाम। श्यामल कुमार सेन (2018) 5 एस. सी. सी. 644; श्रीहरि हनुमंतस टोटला बनाम। हेमंत विठ्ठल कामत (2021) 9 एस. सी. सी. 99; वी. जानकीरामैया चेट्टी बनाम। ए. के. पार्थसारथी और अन्य। (2003) 5 एससीसी 641: [2003] 3 एससीआर 369; प्रकाश चंदर मनचंदा बनाम। जानकी मनचंदा (1986) 4

एस. सी. सी. 699 [1987] 1 एस. सी. आर. 288-पर निर्भर था।

भारत संघ बनाम। नानक सिंह एयर 1968 एस. सी. 1370: [1968] 2 एस. सी. आर. 887; सत्यधन घोषाल और अन्य। वी. श्रीमती. देवराजिन देवी और अन्न। आकाशवाणी 1960 एससी 941: [1960] 3

एससीआर 590; ओम प्रकाश गुप्ता बनाम। रतन सिंह (1964) 1 एस. सी. आर. 259; गुलाबचंद छोटालाल पारिख बनाम। की स्थिति

गुजरात AIR 1965 SC 1153 [1965] SCR 547-संदर्भित

को।

हर दयाल बनाम। राम गुलाम एयर (31) 1944 अवध 39;

नीला वी. पुनन एयर 1936 लाहौर 385; गोविंदोस कृष्णदास बनाम। कार्वेतनगर और अन्न के राजा। ए. आई. आर. 1929 मद्रास 404; प्रतिवादी भयङ्करम पिचम्मा बनाम। के. श्रीरामुलु ए. आई. आर. 1918 मैड 143 (एफ. बी.); मारियानिस्सा बनाम। रामकलपा गोरसिन आई. एल. आर. 34 कैल 235; गोपी किशन बनाम।

रामू, ए. आई. आर. 1964 राज 147; शिद्रमप्पा इरप्पा शिवांगी वी. बसलिंगप्पा कुशनापा कुंभार एयर 1943

बम 321: 1943 एस. सी. सी. ऑनलाइन बम 16: आईएलआर 1944 बम 1 (एफबी); आर. रवींद्रन बनाम। एम. राजमाणिकम 2006 एससीसी ऑनलाइन मैड 169 का उल्लेख किया गया।

मामला कानून संदर्भ

[1968] 2 एससीआर 887

संदर्भित किया गया है

पैरा

22

[1960] 3 एससीआर 590

संदर्भित किया गया है

पैरा

22

(1964) 1 एससीआर 259

संदर्भित किया गया है

पैरा

22

[1965] एससीआर 547

संदर्भित किया गया है

पैरा

22

[2003] 6 पूरक। एससीआर 927

उस पर भरोसा करें

पैरा

26 [2023] 4 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2008] 7 एससीआर 39

उस पर भरोसा करें

पै

रा 28

[2012] 6 एससीआर 404

उस पर भरोसा करें

पै

रा 33

[2003] 3 एससीआर 369

उस पर भरोसा करें

पै

रा 42

[1987] 1 एससीआर 288

उस पर भरोसा करें

पै

रा 47

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय: सिविल अपील सं. 1948

2013 से।

उच्च न्यायालय के 04.05.2010 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2002 के सी. आर. पी. No.1332 में नई दिल्ली में।

मोहन पांडे, मेसर्स. मुकेश कुमार सिंह एंड कंपनी, एड. के लिए
अपीलार्थी।

अजय कुमार तलेसरा, जमशेद बे, मुदित तलेसरा, परविंदर

चौहान, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

जे. बी. पारदीवाला, जे.

यह अपील, विशेष अनुमति द्वारा, मूल आदेश के अनुसार है।

दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम, 1958 (संक्षेप में, 'अधिनियम 1958') के प्रावधानों के तहत दायर एक बेदखली याचिका के वादी (मकान मालिक) को दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पारित फैसले और डिक्री के खिलाफ निर्देशित किया जाता है। 2002 की सिविल पुनरीक्षण याचिका संख्या 1332 में दिनांक 04.05.2010, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी (किरायेदार) द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका को अनुमति दी, जिससे सिविल प्रक्रिया संहिता (सी. पी. सी.) के आदेश 7 नियम 11 के प्रावधानों के तहत वाद को इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि बेदखली याचिका न्यायिक प्रक्रिया के सिद्धांतों द्वारा वर्जित थी।

तथ्यात्मक मैट्रिक्स

2. इस अपील को जन्म देने वाले तथ्यों को संक्षेप में नीचे दिया जा सकता है।

3. यह अपीलार्थियों का मामला है कि यहाँ उत्तरदाता

आवास संख्या 163 (पुरानी संख्या 143) वाली संपत्ति के संबंध में अपीलार्थियों के पिता द्वारा 27.12.1987 पर किरायेदारों के रूप में शामिल किया गया था।

गाँव ढक्का, किंग्सवे कैम्प, दिल्ली में रुपये के मासिक किराए पर। 1050 /

बिजली, पानी और गृह कर को छोड़कर। इसके अनुसार

-

अपीलकर्ताओं ने कहा कि किरायेदारी आवासीय उद्देश्य के लिए थी। यह भी उनका मामला है कि किराया फरवरी, 1993 तक विधिवत भुगतान किया गया था।

4. अपीलार्थियों के पिता ने दिनांकित मांग नोटिस दिया

04.03.1996 पी. आर. ई. एम. किसान और ओ. आर. एस. के हिसाब से किराए के बकाया का दावा करने वाले उत्तरदाताओं पर।

वी. ब्रह्म प्रकाश और ओआरएस। [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

रु. 27,800 / - . अपीलार्थियों के अनुसार, उत्तरदाताओं को विधिवत नोटिस दिया गया था। लेकिन, किराए के बकाया का भुगतान नहीं किया गया।

5. ऊपर उल्लिखित ऐसी परिस्थितियों में, पिता

अपीलकर्ताओं ने अधिनियम 1958 की धारा 14 (1) (ए) के तहत 1996 की बेदखली याचिका संख्या 149 वाली 21.05.1996 पर बेदखली याचिका दायर की।

6. उक्त बेदखली याचिका में, प्रतिवादियों ने अपनी लिखित याचिका दायर की

बयान दिया और मकान मालिक और किरायेदार के संबंधों से इनकार किया।

7. अभिलेख पर सामग्री से यह प्रतीत होता है कि लिखित के बाद

प्रतिवादियों द्वारा मकान मालिक और किरायेदार के संबंधों से इनकार करते हुए बयान दायर किया गया था, वादी पक्षकारों के बीच मकान मालिक और किरायेदार के संबंध को स्थापित करने के उद्देश्य से किराया नियंत्रक के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहे। वादी को मकान मालिक और किरायेदार के संबंध को स्थापित करने के लिए सबूत पेश करने के कई अवसर दिए गए थे। रिकॉर्ड से पता चलता है कि वादी को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अंतिम अवसर 09.09.1997 पर और फिर 01.11.1997 पर दिया गया था।

8. ऊपर उल्लिखित ऐसी परिस्थितियों में, किराया नियंत्रक

निम्नलिखित आदेश दिनांक 27.01.1998 पारित करने के लिए आगे बढ़े:

" 27.1.1998

वर्तमान: याचिकाकर्ता के वकील श्री. चंदर शेखर।

सी. एल. याचिकाकर्ता प्रस्तुत करता है कि आज कोई गवाह नहीं आया है और न ही बुलाया गया। आगे स्थगन के लिए कोई आधार नहीं है। आखिरी मौका

याचिकाकर्ता को 9.9.97 और फिर 1.11.97 पर दिया गया था। फिर भी

याचिकाकर्ता ने गवाह को बुलाने की परवाह नहीं की है।

इस प्रकार पी. ई. बंद है।

चूँकि मकान मालिक किरायेदार का रिश्ता ही विवाद में है और याचिकाकर्ता स्थापित करने के लिए कोई सबूत पेश करने में विफल रहा है

इस तथ्य पर, मेरी राय है कि इसे ठीक करने का कोई मतलब नहीं है

आरई के लिए आगे का मामला। इस प्रकार याचिका को याचिकाकर्ता के रूप में खारिज कर दिया जाता है। वह अपना मामला स्थापित करने में विफल रहा है। फाइल भेजी जाए।

एसडी /

27.1.1998

आर. किरण नाथ

रेंट कंट्रोलर:

"[2023] 4 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

9. यह विवाद में नहीं है कि बेदखली याचिका को खारिज करने वाले उपरोक्त आदेश के खिलाफ कोई अपील नहीं की गई थी। मूल वादी, अर्थात् समी सिंह के जीवन काल के दौरान, कोई नई बेदखली याचिका नहीं

अधिनियम 1958 की धारा 14 (1) (ए) दायर की गई थी।

10. समी सिंह (मूल वादी) की मृत्यु के बाद, हित में उत्तराधिकारी होने का दावा करने वाले अपीलकर्ताओं ने एक और बेदखली दायर की

के खिलाफ 2001 की बेदखली याचिका संख्या 136 के रूप में दर्ज याचिका

अधिनियम 1958 की धारा 14 (1) (ए) के तहत अन्य बातों के साथ-साथ नोटिस जारी होने की तारीख तक किराए के बकाया का दावा करने वाले प्रतिवादी

यानी 18.05.2001 तक। उत्तरदाताओं द्वारा यहां एक लिखित बयान दायर किया गया था जिसमें यह रुख अपनाया गया था कि समी सिंह (पहली बेदखली याचिका का मूल वादी) यानी अपीलकर्ताओं के हित में पूर्ववर्ती पक्षकारों के बीच मकान मालिक और किरायेदार के संबंध को साबित करने में विफल रहा था और ऐसी परिस्थितियों में, इसे दूसरी बेदखली याचिका में फिर से खोलने की अनुमति नहीं दी जा सकती है क्योंकि इसे न्यायिक प्रक्रिया के सिद्धांतों द्वारा बाधित किया जाएगा।

11. ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ उत्तरदाताओं ने सी. पी. सी. के आदेश 7 नियम 11 के प्रावधानों के तहत एक आवेदन को प्राथमिकता दी जिसमें कहा गया था कि

2001 की बेदखली याचिका संख्या 136 को आरक्षण के सिद्धांतों द्वारा वर्जित किया गया था।

न्यायपालिका और शिकायत को तदनुसार खारिज कर दिया जाए।

12. अतिरिक्त किराया नियंत्रक ने शिकायत को अस्वीकार करने से इनकार कर दिया

कानून में मान्य नहीं है। सी. पी. सी. के आदेश 7 नियम 11 (डी) के तहत आवेदन को तदनुसार खारिज कर दिया गया था।

13. अतिरिक्त किराया नियंत्रक द्वारा पारित आदेश से असंतुष्ट उत्तरदाताओं ने सिविल दायर करके इसे चुनौती दी।

दिल्ली उच्च न्यायालय में 2002 की पुनरीक्षण याचिका संख्या 1332।

14. उच्च न्यायालय ने दीवानी पुनरीक्षण याचिका को स्वीकार कर लिया और 2001 की बेदखली याचिका संख्या 136 के वाद को इस आधार पर खारिज कर दिया कि यह न्यायिक प्रक्रिया के सिद्धांतों से प्रभावित था। उच्च न्यायालय जबकि पी. आर. ई. एम. किशोर और ओ. आर. एस.

वी. ब्रह्म प्रकाश और ओआरएस। [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

उत्तरदाताओं द्वारा दायर नागरिक पुनरीक्षण याचिका की अनुमति देते हुए कहा गया है:

" 17. वर्तमान मामले में, एस। समी सिंह, उत्तरदाताओं/मकान मालिकों के हित में पूर्ववर्ती, कोई सबूत पेश करने में विफल रहे।

अधिनियम की धारा 14 (1) (ए) के तहत उसके द्वारा दायर पहली बेदखली याचिका में पक्षकारों के बीच मकान मालिक और किरायेदार के संबंध को स्थापित करने के लिए साक्ष्य। चूंकि उक्त निर्णय किसी भी पक्ष द्वारा अपील में नहीं लिया गया था, इसलिए इसे अंतिम रूप दिया गया। हो चुका है

साक्ष्य का नेतृत्व करने का अवसर देने और न्यायालय में कोई साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफल रहने के कारण, इसे निर्णय के रूप में लिया जाना चाहिए।

सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश XVII नियम 3 के तहत गुण-दोष पर

18. बाद में बेदखली याचिका दायर करके, प्रत्यर्थियों को सीधे ऐसा करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है जो वे अप्रत्यक्ष रूप से नहीं कर सकते थे। साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफलता, जिसके परिणामस्वरूप दावे को खारिज कर दिया जाता है सबूत की कमी के लिए उत्तरदाता, वास्तव में, गुण-दोष पर निर्णय है। मानो याचिकाकर्ता ने उसमें सबूत पेश किया था, जिसे अदालत ने अपर्याप्त सबूत माना था और इसे उक्त आधार पर खारिज कर दिया था। ऐसी स्थिति के लिए कानूनी उक्ति लागू होती है, 'डी नॉन एपेरेंटिबस एट नॉन एक्सिस्टेंटिबस एडम एस्ट रेश्यो'। यह एक ऐसा नियम है जो उन चीजों पर लागू होता है, जो दिखाई नहीं देती हैं, और उन चीजों पर लागू होता है जो मौजूद नहीं हैं। इसलिए, किराए के बकाया का दावा करने के अपने अधिकार को बनाए रखने के लिए, यदि Sh.Samey सिंह को यह साबित करने की आवश्यकता थी कि वह याचिकाकर्ता का मकान मालिक था, लेकिन वह ऐसा करने में विफल रहा, तो किराया नियंत्रक के पास सबूत पेश न करने के कारण उसके खिलाफ मुद्दे का फैसला करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। दूसरे शब्दों में, जो प्रकट नहीं होता है, उसे अस्तित्वहीन माना जाना चाहिए।

19. इन परिस्थितियों में, किराया नियंत्रक दिनांक 27.01.1998 का निर्णय, मामले के गुण-दोष पर निर्णय के रूप में लिया जाना है। केवल इसलिए कि दूसरी बेदखली याचिका में प्रत्यर्थियों द्वारा न केवल उस अवधि के लिए, जिसके लिए पहली बेदखली याचिका दायर की गई थी, बल्कि बाद की अवधि के लिए भी किराए के बकाया का दावा करके कार्रवाई का एक बाद का कारण अनुरोध किया गया है, यह मानने का आधार नहीं हो सकता है कि दूसरी बेदखली याचिका बनाए रखने योग्य थी। पहले की कार्यवाही में पक्षकारों के बीच मकान मालिक और किरायेदार का संबंध स्थापित नहीं हुआ था और यही बात दूसरी याचिका में प्रत्यक्ष रूप से और काफी हद तक जारी है जिसमें किराए के बकाया का दावा करने के लिए आधार उत्तरदाताओं (याचिकाकर्ताओं) का रुख है कि वे [2023] 4 एस. सी. आर. हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इसमें याचिकाकर्ता के जमींदार। किराए पर दिए गए निष्कर्ष

नियंत्रक ने पहली याचिका में पारित अपने आदेश दिनांक 27.01.1998 में कहा है कि
दोष के आधार पर निष्कर्ष माना जाना और निर्णय लिया जाना

गुण-

निर्णायक रूप से, प्रकृति में अंतिम हैं और रेस जुडिकाटा के एक बार के रूप में कार्य करते हैं
उत्तरदाताओं द्वारा पसंद की गई दूसरी निष्कासन याचिका।

20. उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, यह न्यायालय है

कानून के अनुसार और बनाए नहीं रखा जा सकता है। अतः उक्त आदेश यह है कि
रद्द करें। आदेश के तहत याचिकाकर्ता द्वारा दायर आवेदन

अलग रखें और

सी. पी. सी. के सातवें नियम 11 की अनुमति है। यह माना जाता है कि दूसरा निष्कासन

अधिनियम की धारा 14 (1) (ए) के तहत प्रतिवादियों द्वारा दायर याचिका है -

अस्वीकार किए जाने के लिए उत्तरदायी है क्योंकि यह न्यायपालिका के सिद्धांतों द्वारा वर्जित है।
तदनुसार आदेश दिया गया। "

(जोर दिया

गया)

15. उच्च द्वारा पारित उपरोक्त आदेश से असंतुष्ट होना

न्यायालय, अपीलार्थी, के वैध मालिक और मकान मालिक होने का दावा करते हुए

विचाराधीन संपत्ति, इस न्यायालय के समक्ष इसके माध्यम से आई है
वर्तमान अपील।

अपीलार्थियों की ओर से प्रस्तुतियाँ

16. अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील

जोरदार रूप से प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय ने एक गंभीर त्रुटि की
2001 की दूसरी बेदखली याचिका संख्या 136 थी

यह विचार रखते हुए कि

कानून में बनाए रखने योग्य नहीं है क्योंकि यह रेस के सिद्धांतों से प्रभावित था

न्यायपालिका। वह प्रस्तुत करेगा कि शिकायत को सी. पी. सी. के आदेश 7 नियम 11 (डी) के प्रावधानों के
तहत अस्वीकार नहीं किया जा सकता था क्योंकि

रेज़ जुडिकाटा को कानून और तथ्य का एक मिश्रित प्रश्न कहा जा सकता है। वह.

प्रस्तुत करेंगे कि बेदखली याचिका के बाद में कोई आरोप नहीं है

2001 का सं. 136 जिसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि निष्कासन याचिका कानून के किसी भी प्रावधान द्वारा वर्जित है।

17. विद्वान वकील ने आगे कहा कि उच्च न्यायालय

आदेश 17 के नियम 3 के सिद्धांतों को लागू करने में भी त्रुटि हुई

किराया नियंत्रक द्वारा पारित पहले आदेश के रूप में सी. पी. सी. दिनांक 27.01.1998

पहली बेदखली याचिका में गुण-दोष नहीं था और इसलिए कोई निष्कर्ष नहीं निकला।

और किरायेदार जिसे पक्षकारों के बीच बाध्यकारी कहा जा सकता है दूसरी निष्कासन याचिका।

प्रेम किशन और ओआरएस। वी. ब्रह्म प्रकाश और ओआरएस। [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

18. ऊपर उल्लिखित ऐसी परिस्थितियों में, विद्वान वकील प्रार्थना करता है कि उसकी अपील में योग्यता होने के कारण, इसकी अनुमति दी जा सकती है और विवादित आदेश को दरकिनार कर दिया जा सकता है।

प्रत्यर्थी संख्या 1 की ओर से प्रस्तुतियाँ

19. दूसरी ओर, प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से पेश विद्वान वकील ने प्रस्तुत करके वर्तमान अपील का जोरदार विरोध किया। यह कहा जा सकता है कि उच्च न्यायालय द्वारा विवादित आदेश पारित करने में कानून की किसी भी त्रुटि की बात न करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है।

20. वह प्रस्तुत करेगा कि मुकदमे के पहले दौर में, स्वर्गीय समी

सिंह (मूल वादी) को मकान मालिक किरायेदार संबंध स्थापित करने के लिए किराया नियंत्रक द्वारा पर्याप्त समय और अवसर दिए गए थे। हालाँकि, समी सिंह अदालत के सामने पेश होने में विफल रहे और किसी का नेतृत्व करने में भी विफल रहे।

इस संबंध में प्रमाण। ऐसी परिस्थितियों में, किराया नियंत्रक ने बेदखली याचिका को खारिज कर दिया।

21. विद्वान वकील प्रस्तुत करेंगे कि उच्च न्यायालय ने उचित रूप से कहा कि किराया नियंत्रक द्वारा पारित 27.01.1998 दिनांकित आदेश

मुकदमे के पहले दौर में सी. पी. सी. के आदेश 17 नियम 3 के प्रावधानों के तहत कहा जा सकता है और यदि ऐसा है, तो यह निष्कर्ष कि मूल वादी है। ई. समी सिंह मकान मालिक को स्थापित करने में सक्षम नहीं था

किरायेदार संबंध को योग्यता के आधार पर कहा जा सकता है। वह प्रस्तुत करेंगे कि एक बार इस तरह का निष्कर्ष रिकॉर्ड में आ जाने के बाद, अपीलकर्ता बाद में समी सिंह के माध्यम से हित में उत्तराधिकारी के रूप में दावा करते हुए उसी आधार पर एक नई बेदखली याचिका को प्राथमिकता नहीं दे सकते थे क्योंकि यह न्यायिक प्रक्रिया के सिद्धांतों से प्रभावित होगा। वह प्रस्तुत करेंगे कि उच्च न्यायालय ने सी. पी. सी. के आदेश 7 नियम 11 (डी) के प्रावधानों के तहत बेदखली याचिका की शिकायत को सही ढंग से खारिज कर दिया।

22. समर्थन में प्रत्यर्थी संख्या 1 की ओर से उपस्थित विद्वान वकील

प्रस्तुतियों ने निम्नलिखित निर्णयों पर निर्भरता रखी है:

1 .

भारत संघ बनाम। नानक सिंह, आकाशवाणी 1968 एस. सी. 1370:

(1968) 2 एससीआर 887

सत्यधन घोषाल और अन्य। वी. श्रीमती. देवराजिन देवी और

2 .

हर दयाल बनाम। राम गुलाम, आकाशवाणी (31) 1944 अवध 39

3 .

नीला बी. पुनन, ए. आई. आर. 1936 लाहौर 385

4 .

गोविंदोस कृष्णदास बनाम। कार्वेतनगर और अन्न के राजा। ,

5 .

आकाशवाणी 1929 मद्रास 404 [2023] 4 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

6 .

ओम प्रकाश गुप्ता बनाम। रतन सिंह, (1964) 1 एससीआर 259

7. गुलाबचंद छोटालाल पारिख बनाम। गुजरात राज्य, आकाशवाणी

1965 एससी 1153

विश्लेषण

23. पक्षों के लिए विद्वान वकील को सुनने के बाद और

अभिलेख पर सामग्री के माध्यम से, एकमात्र सवाल जो हमारे उपहास के लिए आता है वह यह है कि क्या उच्च न्यायालय को अस्वीकार करने में उचित ठहराया गया था

बेदखली याचिका की इस आधार पर कि दूसरी बेदखली याचिका

रेस जुडिकाटा के सिद्धांतों द्वारा वर्जित।

" 11. शिकायत की अस्वीकृति। अभियोग में खारिज कर दिया जाएगा निम्नलिखित मामले:

(क) जहाँ यह कार्रवाई के कारण का खुलासा नहीं करता है;

न्यायालय द्वारा निर्धारित किया जाना, ऐसा करने में विफल रहता है; (ग) जहाँ दावा की गई राहत को उचित रूप से महत्व दिया गया है, लेकिन शिकायत है -

अपर्याप्त मुद्रांकित कागज पर लौटाया गया, और वादी ने न्यायालय द्वारा आवश्यक स्टाम्प-पेपर की आपूर्ति करने की आवश्यकता है

न्यायालय द्वारा निर्धारित किए जाने वाले समय के भीतर, ऐसा करने में विफल रहता है;

((घ) जहाँ बाद बाद में दिए गए कथन से प्रकट होता है -

किसी भी कानून द्वारा प्रतिबंधित किया जाए;

(ई) जहाँ यह डुप्लिकेट में दाखिल नहीं किया गया है;

बशर्ते कि न्यायालय द्वारा सुधार के लिए निर्धारित समय आवश्यक स्टाम्प-पेपर का मूल्यांकन या आपूर्ति नहीं की जाएगी

विस्तारित जब तक कि न्यायालय, दर्ज किए जाने वाले कारणों से संतुष्ट न हो

कि वादी को किसी अपवादात्मक कारण से रोका गया था मूल्यांकन को सही करने या आवश्यक डाक टिकट की आपूर्ति करने की प्रकृति

न्यायालय द्वारा निर्धारित समय के भीतर, जैसा भी मामला हो, और
कि इस तरह के समय को बढ़ाने से इत्तकार करने से गंभीर अन्याय होगा

वादी "।

(जोर दिया गया)

प्रेम किशन और ओआरएस। वी. ब्रह्म प्रकाश और ओआरएस। [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

25. सी. पी. सी. के आदेश 7 नियम 11 (डी) में प्रावधान है कि वाद को खारिज कर दिया जाएगा "जहां वाद वाद के बयान से प्रतीत होता है

किसी भी कानून द्वारा वर्जित "। इसलिए, यह तय करने के लिए कि क्या मुकदमा किसी कानून द्वारा वर्जित है, यह वाद में बयान है जिसका अर्थ लगाना होगा। इस तरह के आवेदन पर निर्णय लेते समय न्यायालय को केवल उचित सम्मान देना चाहिए। शिकायत में दिए गए बयानों पर। क्या मुकदमा किसी भी कानून द्वारा वर्जित है, यह वाद में दिए गए बयानों से निर्धारित किया जाना चाहिए और यह इसके लिए खुला नहीं है

मामले में लिखित बयान सहित किसी भी अन्य सामग्री के आधार पर मुद्दे का निर्णय लें। आदेश 7 नियम 11 (डी) सी. पी. सी. की व्याख्या पर उदाहरणों का उल्लेख करने के लिए आगे बढ़ने से पहले, हम सी. पी. सी. की धारा 11 का उल्लेख करना अनिवार्य पाते हैं जो न्याय व्यवस्था को परिभाषित करती है:

" 11. न्याय करें। कोई भी न्यायालय ऐसे किसी भी वाद या मुद्दे की सुनवाई नहीं करेगा जिसमें प्रत्यक्ष रूप से और पर्याप्त रूप से जारी किया गया मामला उन्हीं पक्षों के बीच, या उन पक्षों के बीच, जिनके तहत वे या उनमें से कोई भी दावा करता है, एक ही शीर्षक के तहत मुकदमा करने वाले पक्षों के बीच, ऐसे वाद के मुकदमे या उस मुकदमे की सुनवाई करने के लिए सक्षम न्यायालय में, जिसमें ऐसा मुद्दा वाद में उठाया गया है, और उस अदालत द्वारा सुना गया है और अंत में निर्णय लिया गया है। 26. सी. पी. सी. की धारा 11 रेज़ जुडिकाटा के नियम को स्पष्ट करती है: ए

नियम 11. न्यायमूर्ति आर. सी. लाहोटी (तत्कालीन विद्वान मुख्य न्यायाधीश के रूप में), वी. राजेश्वरी बनाम मामले में दो न्यायाधीशों की पीठ के लिए बोल रहे थे। टी. सी. सरवनबाबा, (2004) 1 एस. सी. सी. 551 ने न्यायिक याचिका और उन विवरणों पर चर्चा की जो याचिका को साबित करने के लिए आवश्यक होंगे। न्यायालय ने कहा कि यह न्यायाधिकरण के अनुरोध पर निर्णय लेते समय अभिवचनों, मुद्दों और पूर्व वाद के निर्णय की प्रतियों को संदर्भित करना आवश्यक है:

" 11. रेस जुडिकाटा का नियम वाद के मुकदमे की सुनवाई करने वाले न्यायालय के अधिकार क्षेत्र की जड़ पर प्रहार नहीं करता है। यह सार्वजनिक नीति पर आधारित निर्णय द्वारा रोक लगाने का नियम है कि मुकदमेबाजी को अंतिम रूप दिया जाना चाहिए और इसके लिए किसी को भी दो बार परेशान नहीं किया जाना चाहिए।

एक ही कारण।

सी आरा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एक्स

एक्स

एक्स

एक्स

13. न केवल याचिका को लिया जाना है, बल्कि इसकी पुष्टि भी करनी है -

पिछला मामला। किसी दिए गए मामले में केवल निर्णय की प्रति हो सकती है पिछला मुकदमा
न्यायिक याचिका और फैसले के प्रमाण में दायर किया गया है।

अभिवचनों का विवरण विस्तृत या अपेक्षित विवरणों में होता है

और वे मुद्दे जिन्हें पर्याप्त प्रमाण के रूप में लिया जा सकता है। लेकिन जैसा कि बताया गया है

सैयद मोहम्मद में। सैली लब्बई बनाम। मोहम्मद. हनीफा [(1976) 4

एस. सी. सी. 780] रस जुडिकाटा के प्रश्न को तय करने की मूल विधि पक्षकारों के मामले को
निर्धारित करने के लिए सबसे पहले है जैसा कि उनके मामले में आगे रखा गया है

उनके पिछले मुकदमे की संबंधित दलीलें और फिर यह पता लगाने के लिए कि

उस निर्णय द्वारा जो तय किया गया था जो निर्णय के रूप में कार्य करता है

न्यायपालिका। केवल एक द्वारा अभिवचनों के बारे में अटकलें लगाना जोखिम भरा है

अभिवचनों में लगाए गए आरोपों के पाठ का सारांश

निर्णय में उल्लिखित। गुरबक्स में संविधान पीठ सिंह बनाम। भुरालाल [ए. आई. आर. 1964
एस. सी. 1810: (1964) 7 एससीआर 831]

न्यायपालिका की याचिका और बहिष्कार की याचिका को समान रूप से रखना

सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 2 नियम 2 के तहत, यह अभिनिर्धारित किया गया कि

पिछले वाद में वाद का प्रमाण जो बनाने के लिए निर्धारित किया गया है

बार, रिकॉर्ड पर लाया जाना चाहिए। याचिका मूल रूप से आधारित है।

दोनों मुकदमों में कार्रवाई के कारण की पहचान पर और इसलिए,

यह रक्षा के लिए आवश्यक है जो स्थापित करने के लिए बार को बढ़ाता है

पिछले मुकदमे में कार्रवाई का कारण। इस तरह की दलीलें नहीं छोड़ी जा सकतीं।
केवल अटकलों या अनुमानों द्वारा निर्धारित किया जाना

एक प्रक्रिया द्वारा

कटौती करें कि पिछले अभिवचनों में क्या तथ्य बताए गए थे।

काली कृष्ण टैगोर बनाम में प्रिवी काउंसिल के उनके लॉर्डशिप।

सिकरी। परिषद में भारत के लिए राज्य [(1887-88) 15 IA 186: आईएलआर

16 कैल 173] ने बताया कि रेस जुडिकाटा की याचिका नहीं हो सकती है

यह पता लगाए बिना कि मुद्दे में क्या थे निर्धारित किया गया

पिछले मुकदमे में और क्या सुना गया और निर्णय लिया गया। अनावश्यक है।
इनका पता केवल अभिवचनों को देखकर ही लगाया जा सकता है,

मान लीजिए,

पिछले वाद में मुद्दे और निर्णय "।

(जोर दिया गया)

27. इस न्यायालय ने वी. राजेश्वरी (उपरोक्त) के मामले में टिप्पणी की

न्यायपालिका का नियम बाद के मुकदमे की सुनवाई करने वाले न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के मूल पर प्रहार नहीं करता है। यह एस्टोपल का एक नियम है जिसके आधार पर

मुकदमेबाजी को अंतिम रूप देने की नीति। रेस जुडिकाटा की याचिका

कुछ तथ्यों के प्रमाण पर आधारित और फिर पी. आर. ई. एम. किसान और ओ. आर. एस. पर कानून लागू करना।

वी. ब्रह्म प्रकाश और ओआरएस। [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

इस प्रकार तथ्य पाए गए। इसलिए, यह आवश्यक है कि विश्वास की नींव अभिवचनों में रखी जानी चाहिए और फिर मुद्दे को तैयार किया जाना चाहिए और उस पर विचार किया जाना चाहिए।

28. इस स्तर पर निर्णयों का उल्लेख करना आवश्यक होगा।

जो विशेष रूप से इस प्रश्न से संबंधित है कि क्या वाद-विवाद वाद की अस्वीकृति के लिए आधार या आधार हो सकता है। कमला और अन्य में v. के. टी. ईश्वर सा, (2008) 12 एस. सी. सी. 661, विचारण न्यायाधीश ने विभाजन के लिए एक वाद में वाद की अस्वीकृति के लिए एक आवेदन को अनुमति दी थी और उच्च न्यायालय द्वारा इसकी पुष्टि की गई थी। न्यायमूर्ति एस. बी. सिन्हा ने दो न्यायाधीशों की पीठ की ओर से बोलते हुए सी. पी. सी. के आदेश 7 नियम 11 (डी) के दायरे की जांच की और कहा:

" 21. संहिता के आदेश 7 नियम 11 (डी) का सीमित अनुप्रयोग है। यह.

यह दिखाया जाना चाहिए कि मुकदमा किसी भी कानून के तहत वर्जित है। इस तरह की शिकायत में किए गए कथनों से निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए।

आदेश 7 नियम 11 के विभिन्न खंड, हमारी राय में, नहीं होने चाहिए

मिश्रित। जबकि किसी मामले में, अस्वीकृति के लिए एक आवेदन

अभियोग विभिन्न धाराओं में निर्दिष्ट एक से अधिक आधारों पर दायर किया जा सकता है।

इसके उपखंडों में, उस प्रभाव के लिए एक स्पष्ट निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए

उस उद्देश्य के लिए, कोई जोड़ या घटाव नहीं हो सकता है। अनुपस्थिति। न्यायालय की ओर से अधिकारिता का उपयोग विभिन्न स्थानों पर किया जा सकता है।

चरणों में और संहिता के विभिन्न प्रावधानों के तहत। आदेश 7 नियम

11 संहिता में से एक है, आदेश 14 नियम 2 दूसरा है।

22. संहिता के आदेश 7 नियम 11 (डी) को लागू करने के उद्देश्य से, किसी भी प्रमाण की जांच नहीं की जा सकती है। योग्यता के मुद्दे

जो मामला पक्षों के बीच उत्पन्न हो सकता है वह नहीं होगा

उस स्तर पर न्यायालय के दायरे में। सभी मुद्दे नहीं होंगे विषय-उक्त प्रावधान के तहत एक आदेश का विषय।

(जोर दिया

गया)

न्यायालय ने आगे कहा:

" 23. रेस जुडिकाटा के सिद्धांत, जब आकर्षित होते हैं, तो बाधा डालते हैं संहिता की धारा 12 को ध्यान में रखते हुए एक अन्य वाद। द.

कानून और तथ्य के एक मिश्रित प्रश्न को शामिल करना जो हो सकता है

न केवल वाद की परीक्षा बल्कि अन्य साक्ष्य की भी आवश्यकता होती है।
और पहले के मुकदमे में पारित आदेश को या तो [2023] 4 एस. सी. आर. के रूप में लिया जा सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

प्रारंभिक मुद्दा या अंतिम सुनवाई में, लेकिन, उक्त प्रश्न
सकता है।

उस स्तर पर निर्धारित नहीं किया जा

24. यह कहना एक बात है कि बाद में किए गए कथन

उनका चेहरा कार्रवाई का कोई कारण नहीं बताता है, लेकिन यह अलग बात है

तथ्य या कानून। घटना में, न्यायालय का अधिकार क्षेत्र पाया जाता है किसी भी कानून द्वारा
वर्जित किया जाएगा, जिसका अर्थ है, विषय-वस्तु,

शिकायत की अस्वीकृति के लिए आवेदन पर विचार किया जाना चाहिए। "

(जोर दिया गया)

29. उपरोक्त दृष्टिकोण का लगातार एक पंक्ति में पालन किया गया है

इस न्यायालय के न्यायाधीश। चर्च ऑफ क्राइस्ट चैरिटेबल ट्रस्ट एंड

ए. टी. एन. एल. चैरिटेबल सोसाइटी बनाम पोन्नियम्मन एजुकेशनल ट्रस्ट,

2) 8 एस. सी. सी. 706, न्यायमूर्ति पी. सतशिवम (विद्वान मुख्य न्यायाधीश के रूप में)

) ने दो न्यायाधीशों की पीठ की ओर से बोलते हुए कहा कि:

कार्रवाई के कारण का खुलासा करें, दावा की गई राहत का कम मूल्यांकन किया गया है और
अदालत द्वारा अनुमत समय के भीतर ठीक नहीं किया गया, अपर्याप्त रूप से

मोहर लगी और अदालत द्वारा निर्धारित समय के भीतर ठीक नहीं किया गया, वर्जित

किसी भी कानून द्वारा, आवश्यक प्रतियों को संलग्न करने में विफल रहा और वादी

नियम 9 के प्रावधानों का पालन करने में विफल, अदालत के पास नहीं है उसी को अस्वीकार
करने के अलावा अन्य विकल्प। उपरोक्त का एक पाठ

प्रावधान यह भी स्पष्ट करता है कि आदेश 7 के नियम 11 के तहत शक्ति

संहिता का प्रयोग मुकदमे के किसी भी चरण में या उससे पहले किया जा सकता है।

शिकायत दर्ज करने या समन जारी करने के बाद

प्रतिवादी या मुकदमे के समापन से पहले किसी भी समय।

11. इस स्थिति को इस न्यायालय द्वारा सलीम भाई बनाम में समझाया गया था।

महाराष्ट्र राज्य [(2003) 1 एस. सी. सी. 557], जिसमें
विचार करते हुए, यह निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया था:

संहिता के आदेश 7 नियम 11 पर

(एस. सी. सी पी. 560, पैरा 9)

" 9. आदेश 7 नियम 11 सी. पी. सी. के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि

आर. ई. एम. किसान और ओ. आर. एस. तय करने के लिए प्रासंगिक तथ्यों पर गौर करने की
आवश्यकता है।

वी. ब्रह्म प्रकाश और ओआरएस। [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

बिनि सिङ्गव आर 'जलाइया अभियोगनि बाश्नाफोर। निचली अदालत मुकदमे के किसी भी चरण में आदेश 7 नियम 11 सी. पी. सी. के तहत शक्ति का प्रयोग कर सकती है-शिकायत दर्ज करने से पहले या मुकदमे के समापन से पहले किसी भी समय प्रतिवादी को समन जारी करने के बाद। आदेश 7 के नियम 11 के खंड (ए) और (डी) के तहत एक आवेदन पर निर्णय लेने के उद्देश्यों के लिए

सी. पी. सी., वाद में कथन स्पष्ट हैं; लिखित बयान में प्रतिवादी द्वारा की गई दलीलें पूरी तरह से लिखित होंगी। उस स्तर पर अप्रासंगिक, इसलिए, आदेश 7 नियम 11 सी. पी. सी. के तहत आवेदन पर निर्णय लिए बिना लिखित बयान दाखिल करने का निर्देश प्रक्रियात्मक अनियमितता के बिना नहीं हो सकता है।

विचारण न्यायालय द्वारा अधिकारिता का प्रयोग "।

यह स्पष्ट है कि आदेश 7 नियम 11 पर विचार करने के लिए, अदालत को वाद में दिए गए कथनों पर गौर करना होगा और वही हो सकता है - मुकदमे के किसी भी चरण में निचली अदालत द्वारा प्रयोग किया गया। यह भी स्पष्ट है कि लिखित कथन में किए गए कथन महत्वहीन हैं और वाद में किए गए कथन/याचिकाओं की जांच करना न्यायालय का कर्तव्य है। दूसरे शब्दों में, इस तरह के आवेदन पर निर्णय लेने में जिस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है, वह है वाद में किए गए कथन। उस स्तर पर, लिखित बयान में प्रतिवादी द्वारा की गई दलीलें पूरी तरह से अप्रासंगिक हैं और मामले का निर्णय केवल वादी के कथनों पर किया जाना है। इन सिद्धांतों को राफ्टाकोस ब्रेट एंड कंपनी लिमिटेड बनाम में दोहराया गया है। गणेश संपत्ति [(1998) 7 एस. सी. सी. 184] और मायार (एच. के.) लिमिटेड वी. पोत एम. वी. फॉर्च्यून एक्सप्रेस [(2006) 3

एससीसी 100] "।

30. इसी तरह, सौमित्र कुमार सेन बनाम। श्यामल कुमार सेन, 3) 5 एस. सी. सी. 644, आदेश 7 नियम 11 ई. सी. पी. सी. के तहत एक आवेदन दायर किया गया था जिसमें इस आधार पर शिकायत की अस्वीकृति का दावा किया गया था कि मुकदमा अदालत द्वारा दायर किया गया था। ट्रायल जज ने उस आवेदन को खारिज कर दिया जिसमें ट्रायल कोर्ट के फैसले की अदालत द्वारा पुनरीक्षण में पुष्टि की गई थी। न्यायमूर्ति ए. के. सीकरी ने उच्च न्यायालय के फैसले की पुष्टि करते हुए

, आयोजित:

" 9. पहले उदाहरण में, यह देखा जा सकता है कि जहां तक स्थायी और अनिवार्य निषेधाज्ञा की राहत का संबंध है, वह कार्रवाई के एक अलग कारण पर आधारित है। साथ ही निचली अदालत द्वारा उस तरह की राहत पर तभी विचार किया जा सकता है जब वादी इस तरह का मुकदमा लाने के लिए अपना अधिकार स्थापित करने में सक्षम हो। यदि अपीलार्थी द्वारा अपने लिखित कथन में किए गए कथन सही हैं, तो ऐसे [2023] 4 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

आदेश 7 नियम 11 सी. पी. सी. के तहत। यह संभव है कि चतुराई से तैयार किए गए वाद में वादी ने वाद संख्या 268 के बारे में विवरण नहीं दिया हो। 2008 जो उसके खिलाफ तय किया गया है। उन्होंने 1995 के वाद संख्या 103 के बारे में उल्लेख करना पूरी तरह से छोड़ दिया है, जिस निर्णय ने अंतिमता प्राप्त कर ली है। उस अर्थ में, वादी-प्रतिवादी 1 दमन और छिपाने का दोषी हो सकता है, यदि अपीलार्थी द्वारा किए गए दावे अंततः सही पाए जाते हैं। हालांकि, कानून के स्थापित सिद्धांतों के अनुसार, लिखित बयान में पेश किए गए इस तरह के बचाव को आदेश 7 नियम 11 सी. पी. सी. के तहत आवेदन पर निर्णय लेते समय नहीं देखा जा सकता है।

(जोर दिया गया)

कमला (ऊपर) का उल्लेख करते हुए, न्यायालय ने आगे कहा कि:

" 12. अपीलार्थी ने पहले के दो मामलों का उल्लेख किया है जो प्रतिवादी 1 द्वारा दायर किए गए थे और जिनमें वह विफल रहे थे। ये न्यायिक अभिलेख हैं। अपीलार्थी पहले के दो मुकदमों में अभिवचनों की प्रमाणित प्रतियों के साथ-साथ उन कार्यवाहियों में अदालतों द्वारा पारित निर्णयों की प्रतियां दाखिल करके आसानी से अपने कथनों की शुद्धता का प्रदर्शन कर सकता है। वास्तव में, सिविल जज (जूनियर डिवीजन) द्वारा पारित निर्णय और डिक्री दिनांक 31-3-1997 में पारित आदेशों की प्रतियां, सिविल जज (जूनियर डिवीजन) द्वारा पारित डिक्री को बरकरार रखते हुए सिविल जज (सीनियर डिवीजन) द्वारा पारित निर्णय और डिक्री दिनांक 31-3-1998 की प्रति के साथ-साथ सिविल जज (जूनियर डिवीजन) द्वारा पारित निर्णय और डिक्री दिनांक 31-7-2014 की प्रति। 2008 के वाद सं. 268 में न्यायाधीश, कनिष्ठ प्रभाग को अपीलार्थी द्वारा अभिलेख पर रखा गया है। पहले मुकदमे का फैसला करते समय, निचली अदालत ने एक स्पष्ट निष्कर्ष दिया कि पक्षों के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अनुसार, प्रतिवादी 1 ने रुपये की राशि स्वीकार की थी और इसलिए, उक्त मुकदमे को रोक, छूट और सहमति के सिद्धांतों द्वारा वर्जित किया गया था। इस तरह के मामले में, हालांकि अपीलार्थी द्वारा आदेश 7 नियम 11 सी. पी. सी. का सहारा लेना उचित नहीं था, उसी पी. आर. ई. एम. किसान और ओ. आर. एस. में।

वी. ब्रह्म प्रकाश और ओआरएस। [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

समय, निचली अदालत, मुद्दों को तैयार करने के बाद, ले सकती है

वे मुद्दे जो वाद की अनुरक्षण क्षमता से संबंधित हैं और निर्णय लेते हैं

पहले मामले में भी ऐसा ही है। इस प्रकार से अपीलार्थी, या पक्षकारों को अनावश्यक पीड़ा से मुक्त किया जा सकता है

लंबी कार्यवाही, यदि अपीलार्थी को अंततः पाया जाता है उसकी दलीलों में सही रहें।

(जोर दिया गया)

31. सौमित्र कुमार सेन (ऊपर) के मामले में यह न्यायालय था

एक ऐसे मामले की जांच करते हुए जहां प्रतिवादी ने सी. पी. सी. के आदेश 7 नियम 11 के तहत ट्रायल कोर्ट के समक्ष एक आवेदन दायर किया था, जिसमें अदालत से अनुरोध किया गया था कि वह अभियोग को न्यायिक आधार पर खारिज कर दे। निचली अदालतों ने ऐसी प्रार्थना को खारिज कर दिया था जिस पर प्रतिवादी ने इस अदालत का दरवाजा खटखटाया था। इस न्यायालय ने इस मुद्दे पर अपने विभिन्न निर्णयों का उल्लेख करते हुए ऐसे आदेशों को यह कहते हुए बरकरार रखा कि यदि अपीलार्थी द्वारा लिखित बयान में किए गए कथन सही हैं, तो मुकदमा बनाए रखने योग्य नहीं हो सकता है। हालाँकि, इस स्तर पर, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा उचित रूप से अभिनिर्धारित किया गया है, लिखित में बचाव बयान नहीं दिया जा सकता है। सी. पी. सी. के आदेश 7 नियम 11 के तहत आवेदन पर निर्णय लेने के उद्देश्य से शिकायत पर गौर करना होगा।

32. यह मानते हुए कि "आदेश 7 नियम 11 का सहारा"

अपीलार्थी उचित नहीं था, इस न्यायालय ने कहा कि विचारण न्यायालय

मुद्दों को तैयार करने के बाद, उन मुद्दों को उठा सकते हैं जो मुकदमे की रखरखाव से संबंधित हैं और उन्हें पहली बार में तय कर सकते हैं। न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि इस कार्रवाई से अपीलार्थी को लंबी कार्यवाही से बचने में मदद मिलेगी।

33. उपरोक्त अधिकारियों के अवलोकन पर, मार्गदर्शक सिद्धांत

सी. पी. सी. के आदेश 7 नियम 11 (डी) के तहत आवेदन पर निर्णय लेने के लिए सारांश इस प्रकार दिया जा सकता है:

((i) किसी वाद को इस आधार पर अस्वीकार करना कि मुकदमा किसी भी पक्ष द्वारा वर्जित है।

कानून, केवल वाद में कथनों को संदर्भित करना होगा;

((ii) वाद में प्रतिवादी द्वारा किया गया बचाव नहीं होना चाहिए

आवेदन के गुण-दोष तय करते समय विचार किया जाता है;

((iii) यह निर्धारित करने के लिए कि क्या कोई मुकदमा न्यायिक प्रक्रिया द्वारा वर्जित है, यह है -

यह आवश्यक है कि (i) 'पिछले वाद' का निर्णय लिया जाए, (ii) मामले

पूर्व मुकदमा; (iii) पूर्व मुकदमा उन्हीं पक्षों के बीच था या वे पक्ष जिनके माध्यम से वे दावा करते हैं, एक ही शीर्षक के तहत मुकदमा करते हैं; [2023] 4 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

और (iv) कि इन मुद्दों पर निर्णय लिया गया था और अंत में बाद के मुकदमे का परीक्षण करने के लिए सक्षम अदालत द्वारा निर्णय लिया गया था; और

((iv) चूंकि न्यायिक याचिका के निर्णय के लिए 'पिछले वाद' में अभिवचनों, मुद्दों और निर्णय पर विचार करने की आवश्यकता होती है, इसलिए ऐसी याचिका आदेश 7 नियम 11 (डी) के दायरे से बाहर होगी, जहां केवल वाद में दिए गए बयानों पर ही विचार करना होगा।

(श्रीहरि हनुमंतस टोटल बनाम देखें। हेमंत विठ्ठल कामत,

(2021) 9 एस. सी. सी. 99)

34. सी. पी. सी. की धारा 11 के तहत न्यायिक निर्णय के सामान्य सिद्धांत में निर्णय की निर्णायकता के नियम होते हैं, लेकिन न्यायिक निर्णय के लिए।

लागू करने के लिए, बाद के वाद में प्रत्यक्ष रूप से और पर्याप्त रूप से जारी किया गया मामला वही मामला होना चाहिए जो प्रत्यक्ष रूप से और पर्याप्त रूप से पूर्व के वाद में जारी किया गया था। इसके अलावा, मुकदमे का निर्णय गुण-दोष के आधार पर किया जाना चाहिए था और निर्णय को अंतिम रूप दिया जाना चाहिए था। जहां पहला मुकदमा निचली अदालत द्वारा अधिकारिता के अभाव में, या वादी की उपस्थिति में चूक के लिए, या पक्षों के गैर-सहयोगी या गलत सहयोगी या बहुभिन्नता के आधार पर, या इस आधार पर कि मुकदमा बुरी तरह से तैयार किया गया था, या किसी तकनीकी गलती के आधार पर, या वादी की ओर से जांच या प्रशासन का पत्र पेश करने में विफलता के लिए खारिज कर दिया जाता है या

), निर्णय, गुण-दोष पर नहीं होने के कारण, बाद के मुकदमे में न्यायिक नहीं होगा। 35. वर्तमान मामले में, बेदखली याचिका का विरोध करने के लिए प्रतिवादियों के न्यायिक आधार की जांच करने से पहले, कई पहलू हो सकते हैं

गौर किया जाना चाहिए। क्या इस तरह का मुद्दा महत्वपूर्ण रूप से मुद्दा था पिछले मुकदमे में और इसी तरह के अन्य प्रश्न सामने आ सकते हैं। ऐसी परिस्थितियों में सी. पी. सी. के आदेश 7 नियम 11 के तहत शक्तियां उपलब्ध नहीं होंगी। इसलिए उच्च न्यायालय ने शिकायत को खारिज करने में गलती की।

36. वर्तमान अपील में हमें जो मूल प्रश्न तय करने की आवश्यकता है, वह यह है कि क्या स्वर्गीय समी सिंह द्वारा दायर 1996 का पहला मुकदमा यानी बेदखली याचिका संख्या 149 गुण-दोष के आधार पर खारिज कर दिया गया था। दूसरे शब्दों में कहें तो क्या यह निष्कर्ष किराया नियंत्रक द्वारा दर्ज किया गया है जबकि पी. आर. ई. एम. किशोर और ओ. आर. एस.।

वी. ब्रह्म प्रकाश और ओआरएस। [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

1996 की बेदखली याचिका सं. 149 को खारिज करते हुए कि बेदखली याचिका खारिज की जानी चाहिए क्योंकि वादी समी सिंह ऐसा करने में विफल रहे थे। पक्षकारों के बीच मकान मालिक और किरायेदार के संबंध को योग्यता के आधार पर स्थापित किया जा सकता है ताकि 2001 की दूसरी बेदखली याचिका संख्या 136 को न्यायिक प्रक्रिया के सिद्धांतों पर बनाए रखने योग्य न बनाया जा सके।

37. उच्च न्यायालय ने यह विचार व्यक्त किया कि पहला मुकदमा अर्थात् 1996 की बेदखली याचिका संख्या 149 को सी. पी. सी. के आदेश 17 आदेश 3 के प्रावधानों के तहत खारिज किया जा सकता है और इसलिए, मकान मालिक और किरायेदार के संबंध के संबंध में उसमें दर्ज निष्कर्ष को गुण-दोष के आधार पर कहा जा सकता है और इस प्रकार बाद की कार्यवाही में बाध्यकारी कहा जा सकता है।

38. उपरोक्त संदर्भ में, हम सी. पी. सी. के क्रमशः आदेश 17 नियम 2 और 3 के प्रावधानों पर विचार कर सकते हैं जो इस प्रकार हैं:

" आदेश 17 नियम 2 और 3:

2. यदि पक्ष निर्धारित दिन उपस्थित होने में विफल रहते हैं तो प्रक्रिया। कहाँ, जिस दिन वाद की सुनवाई स्थगित की जाती है, पक्षकार या उनमें से कोई भी उपस्थित होने में विफल रहता है, उस दिन न्यायालय आदेश IX द्वारा उस ओर से निर्देशित तरीकों में से किसी एक में वाद का निपटारा करने के लिए आगे बढ़ सकता है या

ऐसा अन्य ऑर्डर करें जो वह उचित समझे।

स्पष्टीकरण। जहाँ सबूत या एक बड़ा हिस्सा किसी भी पक्ष का साक्ष्य पहले ही दर्ज किया जा चुका है और ऐसा पक्ष किसी भी दिन पेश होने में विफल रहता है जिस दिन मुकदमे की सुनवाई होती है।

स्थगित होने पर, न्यायालय अपने विवेकाधिकार पर मामले को आगे बढ़ा सकता है जैसे कि ऐसा पक्ष उपस्थित था।

3. किसी भी पक्ष के विफल होने के बावजूद न्यायालय आगे बढ़ सकता है

सबूत, आदि का उत्पादन करें। — जहां किसी वाद का कोई पक्षकार, जिसे समय दिया गया है, अपना साक्ष्य प्रस्तुत करने, या अपने गवाहों की उपस्थिति का कारण बनने, या वाद की आगे की प्रगति के लिए आवश्यक कोई अन्य कार्य करने में विफल रहता है, जिसके लिए समय दिया गया है -

अनुमति दी गई है, न्यायालय, इस तरह की चूक के बावजूद, -
(क) यदि पक्षकार उपस्थित हैं, तो मुकदमे पर तुरंत निर्णय लेने के लिए आगे बढ़ें।

या

(ख) यदि पक्षकार अनुपस्थित हैं या उनमें से कोई भी अनुपस्थित है, तो नियम के तहत कार्यवाई करें।

2. "

39. सी. पी. सी. के आदेश 17 नियम 2 में यह प्रावधान है कि जहां, किसी भी दिन जिस पर वाद की सुनवाई स्थगित की जाती है, पक्षकार या उनमें से कोई भी [2023] 4 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उपस्थित होने में विफल रहने पर, न्यायालय किसी एक मामले में मुकदमे का निपटारा करने के लिए आगे बढ़ सकता है। आदेश IX द्वारा उस ओर से निर्देशित मोड़ या ऐसा अन्य आदेश दें जो वह उचित समझे।

40. स्पष्टीकरण सी. पी. सी. के आदेश 17 नियम 2 में जोड़ा गया है।

यह प्रावधान है कि जहां किसी भी पक्ष के साक्ष्य या साक्ष्य का एक बड़ा हिस्सा पहले ही दर्ज किया जा चुका है और ऐसा पक्ष किसी भी दिन पेश होने में विफल रहता है जिस दिन मुकदमे की सुनवाई स्थगित की जाती है, तो न्यायालय अपने विवेकाधिकार पर मामले में आगे बढ़ सकता है जैसे कि ऐसा पक्ष मौजूद था।

41. तथापि, सी. पी. सी. के आदेश 17 नियम 3 में यह प्रावधान है कि जहां किसी वाद का कोई पक्षकार जिसे समय दिया गया है, अपना साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफल रहता है, या अपने गवाहों की उपस्थिति का कारण बनता है, या वाद की आगे की प्रगति के लिए आवश्यक कोई अन्य कार्य करने में विफल रहता है, जिसके लिए समय की अनुमति दी गई है, न्यायालय, इस तरह की चूक के बावजूद, (ए) यदि पक्षकार उपस्थित हैं, तो वाद पर तुरंत निर्णय लेने के लिए आगे बढ़ सकता है, या (बी) यदि पक्षकार हैं, या उनमें से कोई अनुपस्थित है, तो नियम 2 के तहत आगे बढ़ सकता है।

42. सी. पी. सी. के आदेश 17 नियम 2 और आदेश 17 नियम 3 का दायरा बी. के मामले में इस न्यायालय के समक्ष विचार के लिए आया।

जानकीरामैया चेट्टी बनाम। ए. के. पार्थसारथी और अन्या, (2003) 5 एस. सी. सी. 641, जिसमें न्यायमूर्ति अरिजीत पसायत ने पीठ की ओर से बोलते हुए पैरा 7 से 10 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:

" 7. यह निर्धारित करने के लिए कि आदेश 9 के तहत उपचार खो गया है या नहीं, यह देखना आवश्यक है कि क्या पहली बार में न्यायालय ने नियम 2 के स्पष्टीकरण का सहारा लिया था।

8. स्पष्टीकरण अदालत को अपने विवेकाधिकार पर ऐसे मामले में आगे बढ़ने की अनुमति देता है जहां किसी भी पक्ष के साक्ष्य का पर्याप्त हिस्सा पहले ही दर्ज किया जा चुका है और ऐसा पक्ष किसी भी मामले में पेश होने में विफल रहता है।

जिस दिन मुकदमे की सुनवाई स्थगित की जाती है। जैसा कि प्रावधान से ही पता चलता है, अदालत को दी गई विवेकाधीन शक्ति

किसी दी गई परिस्थिति में प्रयोग किया जाता है। प्रावधान के आवेदन के लिए, अदालत को खुद को संतुष्ट करना होगा कि:

(क) किसी भी पक्ष के साक्ष्य का पर्याप्त हिस्सा पहले ही दर्ज किया जा चुका है; (ख) ऐसा पक्ष किसी भी दिन पेश होने में विफल रहा है; और (ग) जिस दिन मुकदमे की सुनवाई स्थगित की जाती है। नियम 2 न्यायालय को आदेश 9 में दिए गए किसी भी तरीके को अपनाने या ऐसा आदेश देने की अनुमति देता है जो वह उचित समझता है जब किसी भी दिन जिस दिन मुकदमे की सुनवाई स्थगित की जाती है, पक्षकार या

उनमें से कोई भी उपस्थित होने में विफल रहता है। स्पष्टीकरण आर. ई. एम. किशोर और ओ. आर. एस. के अपवाद के रूप में है।

वी. ब्रह्म प्रकाश और ओआरएस। [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

न्यायालय निर्दिष्ट नियम के तहत दी गई सामान्य शक्ति, जिसे विवेक प्रदान किया जाता है परीस्थिति के तहत कार्य करेगा अर्थात् जहां साक्ष्य या किसी पक्ष के साक्ष्य का एक बड़ा हिस्सा पहले ही दर्ज किया जा चुका है और ऐसा पक्ष उस तारीख को उपस्थित होने में विफल रहता है जिस तारीख को मुकदमे की सुनवाई स्थगित की गई है। यदि ऐसी तथ्यात्मक स्थिति है, तो न्यायालय अपने विवेकाधिकार पर मान सकता है कि ऐसा पक्ष मौजूद था। आदेश 9 नियम 3 के तहत अदालत आदेश दे सकती है।

निर्देश देते हुए कि मुकदमा तब खारिज किया जाए जब मुकदमा सुनवाई के लिए बुलाए जाने पर कोई भी पक्ष उपस्थित न हो। नियम 2,6 और 8 में निहित मुकदमे को खारिज करने के लिए अन्य प्रावधान हैं। हम मुख्य रूप से नियम 6 द्वारा कवर की गई स्थिति से चिंतित हैं। स्पष्टीकरण में महत्वपूर्ण शब्द "मामले के साथ आगे बढ़ें" हैं। अतः तथ्यों के आधार पर प्रत्येक मामले में यह देखा जाना चाहिए कि क्या स्पष्टीकरण अदालत द्वारा लागू किया गया था या नहीं।

अनुमेय और अनिवार्य नहीं। स्पष्टीकरण एक डीमिंग प्रावधान की प्रकृति में है, जब दी गई परिस्थितियों में, अनुपस्थित पक्ष को उपस्थित माना जाता है।

23] 4 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

10. स्पष्टीकरण में महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति यह है कि "जहां सबूत है।

या किसी पक्ष के साक्ष्य का एक बड़ा हिस्सा "। वहाँ एक है

इस विधायी अभिव्यक्ति में सकारात्मक उद्देश्य। इसका मतलब साफ है। कि अभिलेख पर साक्ष्य इसकी पुष्टि करने के लिए पर्याप्त है

अनुपस्थित पक्ष का रुख और मुकदमे के निपटारे के लिए। अनुपस्थित व्यक्ति

स्पष्टीकरण के तहत कार्य करते हुए मामले के साथ आगे बढ़ सकते हैं यदि वह प्रथम दृष्टया स्थिति है। अदालत को संतुष्ट होना होगा कि

इस अपेक्षित पहलू के बारे में प्रत्येक मामले के तथ्य। यह भी होगा

न्यायालय के लिए इसमें अपनी संतुष्टि दर्ज करना अनिवार्य है।

आवेदन करने के लिए साक्ष्य या साक्ष्य का हिस्सा ले जाया गया है स्पष्टीकरण बिना किसी उद्देश्य के है। अगर सबूत रिकॉर्ड में है

मुकदमे के निपटारे के लिए पर्याप्त है, स्थगित करने की कोई आवश्यकता नहीं है मुकदमा या निर्णय को स्थगित करना।

(जोर दिया

गया)

43. मद्रास उच्च न्यायालय का प्रतिवादी में पूर्ण पीठ का निर्णय

भयंकरम पिचम्मा बनाम। के. श्रीरामुलु, ए. आई. आर. 1918 मैड 143 (एफ. बी.) और मारियानिस्सा बनाम में कलकत्ता उच्च न्यायालय का निर्णय। रामकलपा गोरसिन, आई. एल. आर. 34 कैल 235, गोपी किशन बनाम मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ के विचार के लिए गिर गया। रामू, ए. आई. आर. 1964 राज 147, और बाम्बे उच्च न्यायालय ने शिद्रमप्पा इरप्पा शिवांगी बनाम. बसलिंगप्पा कुशनापा कुंभार, ए. आई. आर. 1943 बम 321

: 1943 एस. सी. सी. ऑनलाइन बम 16: आई. एल. आर. 1944 बम 1 (एफ. बी.)।

44. के मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ

गोपी किशन (ऊपर) को निम्नानुसार देखा गया:

" 8. प्रतिवादी भयंकरम पिचम्मा बनाम। कामिसेट्टी

श्रीरामुलु, ए. आई. आर. 1918 मैड 143 (एफ. बी.), की पूर्ण पीठ मद्रास उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है कि मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश XVII के नियम 2 और 3

सिविल प्रक्रिया संहिता परस्पर अनन्य है। कहाँ का नियम 2 की शर्तों को पूरा किया जाता है भले ही परिस्थितियाँ

नियम 3 द्वारा परिकल्पित हैं और लागू होते हैं, नियम 2 होना चाहिए आवेदन किया। जिन कारणों ने विद्वान न्यायाधीशों को ऐसा करने के लिए राजी किया

यह वरीयता यह है कि जब कोई पक्ष दोनों के रूप में उपस्थित होने में विफल रहा है

कि सबूत पेश करने या कार्य करने में इसकी विफलता थी अनुचित है कि वह अनुपस्थित है और इसलिए, किसी भी आरईएम किसान और ओआरएस की पेशकश करने में असमर्थ है।

वी. ब्रह्म प्रकाश और ओआरएस। [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

साक्ष्य प्रस्तुत करने या वाद की प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करने में विफलता के लिए स्पष्टीकरण।
इक्विटी ने मांग की कि अदालत को आदेश XVII नियम 2 सिविल प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ना चाहिए

[illegible]

मारियानिस्सा बनाम। रामकलपा गोरसिन, आई. एल. आर. 34 कैल 235 पर विचार किया गया सिविल प्रक्रिया संहिता, 1882 की धारा 157 और 158 के बीच संबंध, जो 1908 की सिविल प्रक्रिया संहिता के क्रमशः आदेश XVII नियम 2 और 3 के अनुरूप है और यह विचार व्यक्त किया कि सामग्री का अस्तित्व इसके लिए आवश्यक था

धारा 158 का अनुप्रयोग जो आदेश XVII के नियम 3 से मेल खाता है। इस मामले में मुद्दों को तैयार किया गया था और विभिन्न मामलों के बाद स्थगन मामला 10 मार्च, 1905 को सुनवाई के लिए आया। वादी ने गवाहों के लिए प्रक्रिया मांगी और प्राप्त की, लेकिन चूंकि वे मुकदमे के लिए निर्धारित तिथि पर पेश नहीं हुए, इसलिए वादी ने उनमें से एक के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी करने का अनुरोध किया। इस आवेदन को अस्वीकार कर दिया गया था। वादी के वकील ने अदालत को सूचित किया कि उसके पास पेश होने के लिए आगे कोई निर्देश नहीं है

मामले में और अधीनस्थ न्यायाधीश ने अभियोजन के अभाव में मुकदमा खारिज कर दिया। जब वादी ने धारा 102 (आदेश IX नियम 8) के तहत बर्खास्तगी के आदेश को रद्द करने के लिए आवेदन किया तो प्रतिवादी ने प्रारंभिक आपत्ति जताई कि मुकदमा धारा 102 के तहत नहीं बल्कि धारा 158 (आदेश XVII नियम 3) के तहत खारिज किया गया था और इसके परिणामस्वरूप वादी का उपचार समीक्षा के रूप में था न कि बहाली के लिए। अंततः वादी ने उच्च न्यायालय में अपील की। विद्वान न्यायाधीशों ने कहा, [2023] 4 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" यह स्पष्ट है कि धारा 157 का दायरा काफी अलग है। धारा 158 से। धारा 158 पर विचार किया गया प्रतीत होता है

एक ऐसा मामला जिसमें न्यायालय के पास इसे सक्षम करने के लिए सामग्री है -

मुकदमे के निर्णय के लिए आगे बढ़ें। क्या धारा 158

प्रदान करता है, कि केवल एक पक्ष में चूक करने का तथ्य है

जिसे उसे निर्देशित किया गया था, उसका प्रदर्शन करने से

वादी के मुकदमे को खारिज करना, यदि वह चूक में पक्षकार था, या

प्रतिवादी के खिलाफ दावे की डिक्री, यदि प्रतिवादी वह व्यक्ति था, जिसने डिफॉल्ट किया; शब्द

‘ यद्यपि सु 'च डिफॉल्ट' स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि न्यायालय है

चूक के बावजूद मुकदमे के निपटारे के लिए आगे बढ़ना,

ऐसी सामग्रियों पर जो इससे पहले हैं। दूसरी ओर धारा 157

हाथ, सूट के निपटान की बात करता है, और निस्संदेह शामिल है

जिन मामलों में इससे पहले कोई सामग्री नहीं हो सकती है

न्यायालय गुण-दोष पर निर्णय सुनाने में सक्षम बनाएगा, क्योंकि उदाहरण के लिए, यदि घटना का विचार धारा 97,98,99 खंड में किया गया है

(ए) और 102 होता है, हालांकि, यदि में उल्लिखित आकस्मिकता

धारा 100, खंड (ए) होता है, सामग्री होगी

न्यायालय के समक्ष, और गुण-दोष पर निर्णय।

(जोर दिया गया)

45. हम बॉम्बे के पूर्ण पीठ के फैसले पर भी विचार कर सकते हैं।

शिवरामप्पा इरप्पा शिवांगी (ऊपर) के मामले में अदालत

निम्नलिखित में आयोजित किया गया था:

" आदेश में पक्षों की उपस्थिति के बारे में सामान्य प्रावधान

III, नियम 1, यह है कि एक पक्ष व्यक्तिगत रूप से या किसी मान्यता प्राप्त व्यक्ति द्वारा उपस्थित हो सकता है।

अभिकर्ता या उसकी ओर से उपस्थित होने वाले, आवेदन करने वाले या कार्य करने वाले वकील द्वारा। इन्हें कानून के किसी भी अन्य स्पष्ट प्रावधान के अधीन बनाया जाता है।

ऐसा स्पष्ट प्रावधान आदेश V, नियम 1 में है, जहाँ

एक प्रतिवादी द्वारा उपस्थिति को या तो (ए) व्यक्तिगत रूप से कहा जाता है,

या (बी) एक वकील द्वारा विधिवत निर्देश दिया गया और सभी सामग्री का जवाब देने में सक्षम

मुकदमे से संबंधित प्रश्न, या (ग) एक वकील द्वारा

कोई ऐसा व्यक्ति जो ऐसे सभी प्रश्नों का उत्तर दे सके। के रूप

प्रपत्र संख्या में दिए गए समन। 1 और एपेक्स के 2। बी से पहले तक अनुसूची में भी वही निर्देश होते हैं। अतः कहाँ,

प्रतिवादी व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं होता है और कोई और नहीं है

उसके वकील को निर्देश दें, एकमात्र व्यक्ति जिसके माध्यम से हा कहा जा सकता है

उपस्थित होने के लिए एक वकील है जिसे विधिवत निर्देश दिया जाना चाहिए और सक्षम होना चाहिए

सभी भौतिक प्रश्नों का उत्तर दें। इसलिए, यह इस प्रकार है कि यदि REM KISHORE & ORS।

वी. ब्रह्म प्रकाश और ओआरएस। [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

प्लीडर सुनवाई के किसी भी दिन अदालत में मौजूद होता है लेकिन उसे इस बारे में कोई निर्देश नहीं होता है कि मामले को कैसे आगे बढ़ाया जाए, प्रतिवादी की कोई उपस्थिति नहीं होती है। क्या एक वकील को विधिवत निर्देश दिया गया है

तथ्य का प्रश्न है, लेकिन यदि वह इस आधार पर मुकदमे में भाग लेने से इनकार करता है कि उसके पास कोई निर्देश नहीं है और फिर मुकदमे से पीछे हट जाता है।

स्थगन के लिए आवेदन के बाद या किए बिना, प्रतिवादी के खिलाफ आगे की सभी कार्यवाही एकतरफा हो जाती है। यदि इसके बाद न्यायालय वादी को साक्ष्य देने के लिए कहता है और फिर उसके पक्ष में एक डिक्री पारित करता है, तो इसे एक एकतरफा डिक्री माना जाना चाहिए। प्रतिवादी तब इसे स्थापित करने के लिए आवेदन करने के लिए स्वतंत्र होगा।

आदेश IX, नियम 13 के तहत अलग। "

46. गोपी किशन (उपरोक्त) में राजस्थान उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने एक उदाहरण दिया कि आदेश 17 का नियम 2 या नियम 3 कब लागू होगा।

. हम पूर्ण पीठ की प्रासंगिक टिप्पणियों को निम्नानुसार उद्धृत करते हैं:

" 18. नियम 2 न्यायालय को, किसी पक्ष के अनुपस्थित होने की स्थिति में, आदेश 9 द्वारा निर्देशित तरीकों में से किसी एक में मुकदमे का निपटारा करने या ऐसा अन्य आदेश देने का विवेकाधिकार प्रदान करता है जो वह उचित समझता है। हालांकि, नियम 3 में ऐसी स्थिति की परिकल्पना की गई है जहां एक पक्ष जिसे साक्ष्य प्रस्तुत करने या मुकदमे की आगे की प्रगति के लिए आवश्यक किसी अन्य कार्य के प्रदर्शन के लिए समय दिया गया है और ऐसा पक्ष साक्ष्य प्रस्तुत करने या उस कार्य को करने में विफल रहता है जिसके लिए न्यायालय को अनुमति दी गई थी। इस तरह के चूक के बावजूद मुकदमे पर तुरंत फैसला करने के लिए आगे बढ़ें। जब कोई पक्ष जिसे साक्ष्य प्रस्तुत करने या किसी अन्य कार्य के निष्पादन के लिए समय दिया गया है, वह भी प्रकट नहीं होता है तो यह स्पष्ट रूप से दोहरे चूक का मामला है। केवल पार्टी ही नहीं

वह ऐसा करने में विफल रहा है जिसके लिए उसे समय दिया गया था लेकिन वह उपस्थित होने में भी विफल रहा है। हमारी राय में यह दोहरी चूक मामले को आदेश XVII नियम 3 के दायरे से दूर नहीं करती है। हम पूर्ण पीठ मद्रास मामले में दी गई व्याख्या से सहमत नहीं हैं कि नियम 2 और 3 परस्पर अनन्य हैं। हमारे सामने भी ऐसे मामले हो सकते हैं, जिनमें किसी पक्ष को साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए समय दिया गया था, लेकिन पक्ष न केवल साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफल रहा, बल्कि खुद भी अनुपस्थित रहा और यह नहीं कहा जा सकता कि आदेश ऐसे मामले में XVII नियम 3 लागू नहीं हो सकता है।

19. विभिन्न कारणों से कलकत्ता उच्च न्यायालय के दृष्टिकोण को अपनाने वाले निर्णयों की एक लंबी श्रृंखला में यह माना गया है कि अस्तित्व

आदेश XVII [2023] 4 एस. सी. आर. के तहत एक मुकदमे का निर्णय लेने के लिए सामग्री की आवश्यकता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

नियम 3. कानून की भाषा स्पष्ट रूप से इसके लिए एक आवश्यक शर्त के रूप में सामग्री के अस्तित्व का संकेत नहीं देती है आवेदन। यह व्याख्या स्पष्ट रूप से 'निर्णय' शब्द से प्रभावित हुई है जिसका अर्थ है गुणों पर निर्णय लेना। रामकरण के मामले, आई. एल. आर. (1953) 3 राज 798 में इस न्यायालय के विद्वान न्यायाधीशों ने महसूस किया कि

सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश XX नियम 4 के प्रावधानों द्वारा यह मानने के लिए राजी किया गया कि सामग्री का अस्तित्व आवश्यक था और क्योंकि केवल अभिवचन और मुद्दे रिकॉर्ड में थे, उन्होंने राय दी कि बर्खास्तगी को आदेश XVII नियम 2 के तहत एक माना जाना चाहिए। दूसरी ओर अमरसिंह के मामले में 1953 में राज एल. डब्ल्यू.

365, विद्वान न्यायाधीशों का विचार था कि जहां वादी मुकदमे में उस पर लगाए गए बोझ का निर्वहन करने में विफल रहता है, तो तार्किक निष्कर्ष यह था कि मुकदमे को खारिज कर दिया जाना चाहिए चाहे सामग्री मौजूद हो या नहीं। किसी भी निर्णय ने आदेश XVII नियम 3 के संचालन के लिए आवश्यक सामग्री की सटीक मात्रा को इंगित करने का प्रयास नहीं किया है। इस तरह के कार्य की कठिनाई आसान है सराहना करें। विभिन्न प्रकार के मामलों और स्थिति की जटिलताओं में सार्वभौमिक नियमों का निर्माण एक ऐसा कार्य है जिसे प्राप्त करना आसान नहीं है। हालाँकि, संकेत रामकरण के मामले, आई. एल. आर. (1953) 3 राज 798 में हैं कि सामग्री का अर्थ रिकॉर्ड पर 'सबूत' हो सकता है। इसके बाद जो स्पष्ट सवाल उठता है वह यह है कि क्या साक्ष्य की अनुपस्थिति आदेश XVII नियम 3 की प्रयोज्यता को पूरी तरह से बाहर कर सकती है? इस तरह के व्यापक प्रस्ताव को निर्धारित करना मुश्किल है।

जैसा कि देखा गया है कि आदेश XVII नियम 3 का इरादा यह है कि एक पक्ष साक्ष्य प्रस्तुत करने या मुकदमे की प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए कुछ करने के लिए समय मांगता है और दोनों में से किसी एक को करने में चूक करता है, एक अदालत मुकदमे का तुरंत फैसला कर सकती है। हमारे विचार से, यह कहना बहुत व्यापक है कि किसी भी मामले में जहां सबूत नहीं दिया गया है

नियम 3 लागू नहीं होगा। परीक्षण यह होना चाहिए कि क्या वह न्यायालय जिसके समक्ष सामग्री के आधार पर मुकदमा लंबित है इससे पहले कि वह मुकदमे पर तुरंत निर्णय लेने की स्थिति में हो, किसी पक्ष की चूक के बावजूद। पक्षकारों की दलीलें और मुद्दे

कुछ मामलों में इससे उत्पन्न होने से न्यायालय मुकदमे पर तुरंत निर्णय लेने में सक्षम हो सकता है। मान लीजिए कि एक वचन पत्र पर एक मुकदमे में जिसके निष्पादन से प्रतिवादी द्वारा इनकार नहीं किया गया है और प्रतिवादी साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए समय मांगने पर विचार करने का अनुरोध करता है। समय की अनुमति है लेकिन वह सबूत पेश करने में चूक करता है। क्या परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 118 में निहित कानूनी अनुमान को ध्यान में रखते हुए मुकदमे का फैसला नहीं किया जा सकता है?

इसके विपरीत REM KISHORE & ORS। वी. ब्रह्म प्रकाश और ओआरएस। [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

मामला प्रतिवादी निष्पादन से इनकार करता है और वादी को निष्पादन साबित करने के लिए समय दिया जाता है और वह चूक करता है। क्या वाद का निर्णय वादी द्वारा किए गए चूक के आधार पर नहीं किया जा सकता है

उस पर रखे गए सबूत के बोझ का निर्वहन करना? सबसे पहले

उदाहरण में शायद यह कहा जा सकता है कि वचन पत्र निष्पादन जिसमें स्वीकार किया गया है, सबूत का गठन करता है और वहाँ है

नियम 3 की प्रयोज्यता को आकर्षित करने के लिए अभिलेख पर सामग्री। दूसरे चित्रण में; हालाँकि, फांसी को स्वीकार नहीं किया गया है, स्पष्ट रूप से कोई सबूत नहीं है। वादी अपना कर्तव्य निभाने में विफल रहता है। क्या हम कह सकते हैं कि मुकदमे का निपटारा आदेश XVII नियम 2 के अनुसार आदेश IX के अनुसार किया जाना चाहिए? इसका उत्तर स्पष्ट रूप से नकारात्मक है क्योंकि आदेश IX के तहत परिकल्पित परिस्थितियाँ चित्रण में दी गई स्थितियों से अलग हैं। क्या यह कहा जा सकता है कि न्यायालय ऐसा अन्य आदेश पारित कर सकता है जो वह आदेश 17 के नियम 2 में निर्धारित करता है? ऐसा आदेश इस तरह की स्थिति में वादी की अनुपस्थिति के लिए मामले को स्थगित करने के अलावा और कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए, यदि वादी अवसर दिए जाने के बावजूद अभिवचनों और परिणामी मुद्दों को देखते हुए उस पर लगाए गए बोझ का निर्वहन करने में विफल रहता है, तो मामले को उसके साक्ष्य के लिए अनंत काल तक स्थगित नहीं किया जा सकता है और किसी न किसी स्तर पर न्यायालय को साक्ष्य के अभाव में इसका निर्णय लेना पड़ता है। यहाँ तक कि एक विवादित मुकदमे में भी कभी-कभी सबूतों के अभाव में मुद्दों का फैसला किया जाता है और इसी तरह पूरा मुकदमा भी हो सकता है। इसलिए, हमारी राय में सामग्री के अस्तित्व का मतलब आवश्यक रूप से साक्ष्य का अस्तित्व नहीं है। यदि किसी वाद का निर्णय उसके समक्ष सामग्री पर साक्ष्य की कमी के बावजूद किया जा सकता है तो आदेश XVII नियम 3 को मामले को नियंत्रित करने के लिए कहा जा सकता है। अभिलेख पर सामग्री को तकनीकी अर्थ देने की आवश्यकता नहीं है और इसके बराबर है -

सबूत। प्रत्येक मामले की परिस्थितियाँ न्यायालय में निहित विवेकाधिकार के प्रयोग को विनियमित करेंगी। यह न्यायालय को अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करना है और बिना अस्पष्टता के यह इंगित करना है कि वह आदेश XVII नियम 3 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग कर रहा है या नहीं। यह सही है कि नियम 3 का आवेदन एक चूक करने वाले पक्ष के भविष्य के उपायों को प्रतिबंधित करता है और एक सख्त प्रावधान है, और इसलिए, इसे सावधानी और न्यायिक संयम के साथ लागू किया जाना चाहिए, इसलिए रामकरण के मामले, आई. एल. आर. (1953) 3 राज 798 को उपरोक्त संशोधन के साथ पढ़ना होगा। हालाँकि, कोई अपवाद नहीं हो सकता है अमरसिंह के मामले, 1953 राज एल. डब्ल्यू. 365 में अपनाए गए तर्क पर ध्यान दिया गया।

(जोर दिया गया)

23] 4 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

परिणामस्वरूप उसे अवसर दिए जाने के बावजूद, मामले को उसके साक्ष्य के लिए अनंत काल तक स्थगित नहीं किया जा सकता है और अदालत को किसी न किसी स्तर पर साक्ष्य के अभाव में निर्णय लेना चाहिए। पूर्ण पीठ ने यह विचार रखा कि सामग्री के अस्तित्व का मतलब यह नहीं होगा कि साक्ष्य का अस्तित्व। यदि वाद का निर्णय उसके समक्ष मौजूद सामग्री पर साक्ष्य की कमी के बावजूद किया जा सकता है, तो ऐसी परिस्थितियों में सी. पी. सी. का आदेश 17 नियम 3 मामले को नियंत्रित करेगा।

48. राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा दी गई उपरोक्त उक्ति इस मामले में इस न्यायालय के निर्णय के विपरीत प्रतीत होती है -

प्रकाश चंदर मनचंदा बनाम। जानकी मनचंदा, (1986) 4 एस. सी. सी. 699, जिसमें इस न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की:

" 6. यह स्पष्ट है कि ऐसे मामलों में जहां कोई पक्ष अनुपस्थित है, केवल पाठ्यक्रम जैसा कि आदेश 17 (3) (बी) में नियम 2 के तहत आगे बढ़ने के लिए उल्लेख किया गया है। इसलिए यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी की अनुपस्थिति में, न्यायालय के पास नियम 2 के तहत आगे बढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, इसी तरह नियम 2 की भाषा जो अब है, यह भी स्पष्ट रूप से बताती है कि यदि कोई भी पक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो न्यायालय को आदेश 9 के तहत निर्देशित तरीकों में से एक में मुकदमे का निपटारा करने के लिए आगे बढ़ना होगा। नियम 2 का स्पष्टीकरण न्यायालय को नियम 3 के तहत आगे बढ़ने का विवेकाधिकार देता है, भले ही कोई पक्ष अनुपस्थित हो, लेकिन यह विवेकाधिकार केवल उन मामलों में सीमित है जहां एक पक्ष जो अनुपस्थित है, ने कुछ साक्ष्य का नेतृत्व किया है या अपने साक्ष्य के पर्याप्त हिस्से की जांच की है। इसलिए यह स्पष्ट है कि यदि किसी निश्चित तिथि पर कोई एक पक्ष अनुपस्थित रहता है और उस पक्ष के लिए उस तिथि तक किसी भी साक्ष्य की जांच नहीं की गई है, तो न्यायालय के पास सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 9 के तहत निर्धारित तरीकों में से किसी एक में आदेश 17 नियम 2 के अनुसार मामले का निपटारा करने के लिए आगे बढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। इसलिए यह स्पष्ट है कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 17 नियम 2 और 3 में इस संशोधन के बाद कोई संदेह नहीं है और इसलिए किसी भी विवाद की कोई संभावना नहीं है। मामले के इस दृष्टिकोण से यह स्पष्ट है

कि जब 30 अक्टूबर 1985 को वर्तमान मामले में जब मामला बुलाया गया था, तो प्रतिवादी के लिए कोई भी उपस्थित नहीं था। यह भी है स्पष्ट करें कि उस तारीख तक वादी का साक्ष्य दर्ज किया गया है लेकिन प्रतिवादी के लिए कोई सबूत दर्ज नहीं किया गया था। प्रतिवादी को केवल इस तारीख या पहले की तारीख को शुरू करना था जब मामला स्थगित कर दिया गया था। इसलिए यह स्पष्ट है कि 30 अक्टूबर, 1985 की तारीख तक जब निचली अदालत ने प्रतिवादी का मामला बंद कर दिया था, तब तक पी. आर. ई. एम. किशोर और ओ. आर. एस. था।

वी. ब्रह्म प्रकाश और ओआरएस। [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

प्रतिवादी की ओर से रिकॉर्ड पर कोई सबूत नहीं है। इस दृष्टि से

इसलिए आदेश 17 नियम 2 का स्पष्टीकरण नहीं था

बिल्कुल लागू होता है। जाहिरा तौर पर जब प्रतिवादी अनुपस्थित था आदेश

17 नियम 2 ने केवल न्यायालय को निपटान के लिए आगे बढ़ने की अनुमति दी

आदेश 9 के तहत प्रदान किए गए तरीकों में से किसी एक में मामला।

7. यह भी स्पष्ट है कि आदेश 17 नियम 3 लागू नहीं था।

इस मामले के तथ्यों को उस तारीख को स्वीकार किया गया जब

प्रतिवादी का साक्ष्य बंद कर दिया गया था कोई भी पक्ष में पेश नहीं हुआ

प्रतिवादी। मामले के इस दृष्टिकोण में यह विवादित नहीं किया जा सकता है कि

न्यायालय जब गुण-दोष के आधार पर वाद का निपटारा करने के लिए आगे बढ़ा तो उसने

एक गलती की। दुर्भाग्य से समीक्षा आवेदन पर भी,

विद्वत विचारण न्यायालय आदेश 17 के बारे में विवाद में चला गया

नियम 2 और 3 जो संशोधन से पहले मौजूद थे और खारिज कर दिए गए थे

समीक्षा आवेदन और अपील पर, उच्च न्यायालय भी
दुर्भाग्य से अपील को एक शब्द में खारिज कर दिया गया।

(जोर दिया

गया)

49. इस प्रकार प्रकाश चंदर में इस न्यायालय द्वारा दिया गया आदेश

मनचंदा (ऊपर) यह है कि साक्ष्य के अभाव में भी नियम 3 के तहत आगे बढ़ना न्यायालय के विवेकाधिकार के भीतर होगा, लेकिन ऐसा विवेकाधिकार केवल उन मामलों में सीमित है जहां एक पक्ष जो विरोध कर रहा है उसने कुछ साक्ष्य का नेतृत्व किया है या पर्याप्त भाग की जांच की है।

50. आइए हम इस न्यायालय द्वारा निर्धारित उपरोक्त उक्ति को लागू करें

वर्तमान मामले के तथ्य। मामले में, पहली बेदखली याचिका दायर किए जाने के बाद, प्रतिवादियों ने मकान मालिक और किरायेदार के संबंधों से इनकार करते हुए अपना लिखित बयान दायर किया। लिखित बयान के रिकॉर्ड में आने के बाद, वादी द्वारा आगे कोई सबूत नहीं दिया गया। जो कुछ भी अभिलेख में था वह शिकायत में दलीलों के रूप में था। अतिरिक्त किराया नियंत्रक का विचार था कि लिखित बयान के रिकॉर्ड में आने के बाद, यह वादी का कर्तव्य था कि वह मकान मालिक किरायेदार के संबंध को स्थापित या साबित करे और

कोई सबूत पेश करने में विफल रहने के बाद, मुकदमा खारिज होने योग्य था और तदनुसार खारिज कर दिया गया था। उच्च न्यायालय ने अतिरिक्त किराए के आदेश की व्याख्या या बल्कि व्याख्या की

आदेश 17 के नियम 3 के तहत एक नियंत्रक के रूप में और इसलिए, यह विचार लिया कि मकान मालिक और किरायेदार के संबंधों के संबंध में निष्कर्ष को गुण-दोष के आधार पर कहा जा सकता है।

51. हमें डर है, उच्च न्यायालय ने लेने में गलती की

यह विचार कि अतिरिक्त किराया नियंत्रक द्वारा पारित आदेश [2023] 4 एस. सी. आर. हो सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

कहा जाए कि सी. पी. सी. के आदेश 17 के नियम 3 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए पारित किया गया है।

52. के आदेश 17 के नियम 3 के तहत न्यायालयों को प्रदत्त शक्ति

डिफ़ॉल्ट होने के बावजूद नियमित तरीके से। नियम 2 और 3 क्रमशः केवल प्रावधानों को सक्षम कर रहे हैं। गुण-दोष के आधार पर वाद का निर्णय करने के लिए केवल नियम 3 में उल्लिखित शर्तों का अस्तित्व ही पर्याप्त नहीं होगा। गुण-दोष पर निर्णय लेने के लिए कुछ सामग्री होनी चाहिए, भले ही सामग्री की तकनीकी रूप से साक्ष्य के रूप में व्याख्या नहीं की जा सकती है। कभी-कभी ऐसे मामलों में निर्णय दलीलों, दस्तावेजों और सबूत के बोझ के आधार पर हो सकता है। फिर भी, न्यायालय के लिए यह सराहनीय है कि वह निर्णय द्वारा यह इंगित करे कि निर्णय चूक के लिए या गुण-दोष पर है। नियम 3 द्वारा कवर किए गए मामलों में या नियम 2 के स्पष्टीकरण में न्यायालय का एकमात्र विकल्प केवल गुण-दोष पर निर्णय लेना नहीं है। यदि ऐसी व्याख्या दी जाती है, तो यह जानबूझकर करने वाले के लिए एक अनुचित वरीयता होगी। उस व्यक्ति की तुलना में अनुपस्थित जो पेश करता है लेकिन मामले को आगे बढ़ाने में असमर्थ है। रूप 'और' उपस्थिति 'के अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त अर्थ हैं। वे व्यक्तिगत रूप से या मामले के संचालन के उद्देश्य से उचित रूप से अधिकृत वकील के माध्यम से उपस्थिति का संकेत देते हैं। नियम 3 केवल तभी लागू होता है जब उपस्थिति मामले के साथ आगे बढ़ने के लिए होती है, लेकिन नियम 2 में उल्लिखित तीन तरीकों में से किसी एक में डिफ़ॉल्ट किया जाता है या नियम 2 का स्पष्टीकरण निकाला जाता है। वे ऐसे मामले हैं जिनमें अदालत के पास गुण-दोष के आधार पर मामले का फैसला करने के लिए कुछ सामग्री है न कि ऐसे मामले जहां निर्णय केवल चूक के लिए हो सकता है। यह क्रमशः नियम 2 और 3 के संयुक्त अध्ययन और स्पष्टीकरण से स्पष्ट है। इस मामले में, इनमें से कोई भी शर्त मौजूद नहीं थी और निर्णय स्पष्ट रूप से चूक के लिए था। केवल नियम 2 ही आकर्षित करता है। (देखू: आर. रवींद्रन बनाम एम. राजमाणिकम, 2006 एससीसी ऑनलाइन मैड 169)

53. इस निर्णय के पैरा 8 में निर्दिष्ट किराया नियंत्रक द्वारा दिनांकित 27.01.1998 द्वारा पारित आदेश का भी एक अलग कोण है। आइए हम एक बार फिर किराया नियंत्रक द्वारा पारित आदेश को बारीकी से पढ़ें। आदेश दो भागों में है। पहले भाग में किराया नियंत्रक कहता है कि पी. आर. ई. एम. किसान और ओ. आर. एस.।

वी. ब्रह्म प्रकाश और ओआरएस। [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

वादी का वकील मौजूद है। फिर, वह यह देखने के लिए आगे बढ़ता है कि वादी के वकील ने एक बयान दिया कि आज कोई गवाह नहीं आया है और न ही उन्हें बुलाया गया है। किराया नियंत्रक ने आगे कहा कि किसी भी आधार पर आगे के स्थगन के लिए अनुरोध नहीं किया गया है।

इसके बाद, वह कहता है कि वादी को अंतिम अवसर 09.09.1997 पर और उसके बाद 01.11.1997 पर दिया गया था। हालाँकि, वादी ने अपने गवाहों को बुलाने की परवाह नहीं की। ऐसी परिस्थितियों में किराया नियंत्रक ने बेदखली याचिका की कार्यवाही बंद कर दी। किराया नियंत्रक द्वारा दिनांकित 27.01.1998 क्रम में उपयोग किए गए सटीक शब्द हैं: इस प्रकार पी. ई. बंद है। आदेश के दूसरे भाग में, किराया नियंत्रक, इसके बाद, यह देखने के लिए आगे बढ़ता है कि चूंकि मकान मालिक-किरायेदार का संबंध विवाद में है और वादी इस तरह के संबंध को स्थापित करने के लिए कोई सबूत पेश करने में विफल रहा है, इसलिए उसे सबूत दर्ज करने के लिए मामले को आगे बढ़ाने का कोई अच्छा कारण नहीं मिला। ऐसी परिस्थितियों में, उन्होंने बेदखली याचिका को खारिज कर दिया, क्योंकि कहा जा सकता है कि वादी अपना मामला स्थापित करने में विफल रहा है। अंत में, उन्होंने देखा कि फाइल को भेज दिया जाए।

54. मामले की सुनवाई के चरण में, सी. पी. सी. के आदेश 17 ने आवेदन किया। उस आदेश के तहत, स्थगित सुनवाई की तारीख पर, यदि कोई पक्ष अनुपस्थित था, तो न्यायालय या तो आदेश 9 के तहत या अन्यथा कार्य करेगा।

वाक्यांश विज्ञान और इसे इसके सामान्य अर्थ से अलग नहीं किया जा सकता है। इसका सामान्य अर्थ यह है कि कार्यवाही बंद कर दी गई थी और मुकदमे को लंबित नहीं माना जाएगा। बाद का विवरण अनावश्यक होगा यदि आदेश मुकदमे के अंतिम निपटान में से एक था। आदेश का उद्देश्य मुकदमे का अंतिम निपटान नहीं था। इसने केवल कार्यवाही को रोक दिया।

कुछ नहीं किया [2023] 4 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अधिका. यह सी. पी. सी. के आदेश 9 नियम 8 और आदेश 17 नियम 3 के जवाब के अर्थ के भीतर मुकदमे का अंतिम निर्णय नहीं है।

56. परिणामस्वरूप, अपील सफल हो जाती है और इसके द्वारा इसकी अनुमति दी जाती है। इसलिए विवादित निर्णय और डिक्री को दरकिनार कर दिया जाता है। अनावश्यक है।

दो चीजें जोड़ें। सबसे पहले, हमने प्रति न्यायिक सिद्धांत की प्रयोज्यता या अन्यथा या उस मामले के लिए लंबित मुकदमे में किसी अन्य विवादास्पद मुद्दे के बारे में प्रतिद्वंद्वी दलीलों पर कोई राय व्यक्त नहीं की है। दूसरा, इस निर्णय में कहा गया कुछ भी संबंधित प्रतिवादियों को अदालत से इस तरह के मुद्दे पर निर्णय लेने का अनुरोध करने से नहीं रोकेगा।

प्रारंभिक मुद्दा। इस तरह के आवेदन पर स्पष्ट रूप से इसके गुण-दोष के आधार पर निर्णय लिया जाएगा, जिसके बारे में भी हमने कोई राय व्यक्त नहीं की थी। सूट को पुनर्जीवित किया जाता है।

57. लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

58. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का भी निपटारा कर दिया जाता है।

अपील की अनुमति दी गई।

अंकित ज्ञान (सहायक: शिवेश रघुवंशी और महेंद्र यादव, एलसीआरएएस)